वर्ष : 16 ❖ अंक : 229 ❖ पृष्ठ : 08 ❖ मूल्य : ₹ 3.00 ❖ आरएनआई सं. SIKHIN/2006/17890 ❖ www.anugamini.com

सिक्किम से प्रकाशित प्रथम हिन्दी दैनिक

अनुगामिनी

गंगटोक
शुक्रवार, 01 अप्रैल 2022

पेट्रोल-डीजल की कीमतें नियंत्रित करे सरकार : राहुल गांधी 3

केंद्र ने नागालैंड, असम और मणिपुर में अफस्पा का क्षेत्र घटाया : शाह 8

विधानसभा में उठा सीबीआई को प्रवेश की अनुमति देने का मुद्दा

राज्य सरकार की ओर से छानबीन पूरी होने के बाद सीबीआई को बुलाया जाएगा : सीएम

डीटी लेप्चा ने किया सवाल- कब होगा विधानसभा का सीधा प्रसारण

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 31 मार्च । सिक्किम विधानसभा के बजट अधिवेशन में एक बार फिर सीबीआई जांच का मुद्दा उठा है। विधायक डीआर थापा और विधायक वाईटी लेप्चा ने आज बजट अधिवेशन पर चर्चा में शामिल होने के दौरान यह मुद्दा उठाया। वहीं सदन के सदस्यों द्वारा सीबीआई जांच का मुद्दा उठाने पर मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) ने बताया कि छानबीन पूरी होने के बाद अवश्य ही सीबीआई को बुलाया जायेगा।

गौरतलब है कि विधायक थापा ने वर्तमान में सिक्किम में भ्रष्टाचार तथा कमीशन प्रथा को बड़ी बीमारी बताते हुए मौजूदा सरकार द्वारा पहले सीबीआई से जांच कराने की बात कहे जाने का उल्लेख करते हुए सरकार से इस सम्बंध में सवाल किया था। वहीं विधायक लेप्चा द्वारा उठाई गई मांग पर बोलते हुए मुख्यमंत्री गोले ने जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री पर आय से अधिक संपत्ति का मामला सीबीआई तक पहुंचने पर उन्होंने राज्य में सीबीआई को प्रवेश से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेने का प्रावधान बनाया था। इसके अनुसार सीबीआई ने पूर्व राज्य सरकार से अनुमति मांगी भी थी, लेकिन उसे जांच की अनुमति नहीं दी गयी।

इस दौरान विधायक आदित्य गोले द्वारा ईक्यूयूआईपी के विषय में किये गये प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री तमांग ने बताया कि इस सम्बंध में सरकार के पास कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस सम्बंध में कोई जांच की मांग करता है, तो सरकार उसके लिये तैयार है।

विधायक पिन्चो नामग्याल लेप्चा ने 2014 तथा 2019 के आम चुनावों के पहले जनता को घर बनाकर देने सम्बंधी अलॉटमेंट ऑर्डर के सम्बंध में प्रश्न पूछा। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जो स्वयं को विधानसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य बताते हैं ने इस प्रकार का झूठा कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने इस प्रकार के अलॉटमेंट ऑर्डर निकाल कर जनता को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार वास्तविक लाभार्थियों का चयन कर उन्हीं को घर बना कर देने का काम कर रही है।

इसी प्रकार विधायक डीटी लेप्चा द्वारा लिम्बू-तमांग जनजाति हेतु सीट आरक्षण के विषय में पूछे गये सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री गोले ने पूर्व सरकार पर इस मसले पर गम्भीर न रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार की लापरवाही के कारण ही यह मुद्दा अनसुलझा रहा। साथ ही उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि इस सम्बंध में सीमांकन आयोग ने पूर्व सरकार के साथ पत्राचार किया था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसकी अवहेलना की। यही नहीं, तत्कालीन सरकार ने इस मुद्दे को टालने के लिये उलटे पत्र भी लिखा था। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार इस मुद्दे पर काम कर रही है और इसका जल्द समाधान निकाला जाएगा।

विधायक डीटी लेप्चा द्वारा विधानसभा की प्रक्रिया का सीधा प्रसारण करने सम्बंधी मांग के सम्बंध में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) ने कहा कि यह मसला विधानसभा के पटल पर विचाराधीन है। वहीं रोजगार के मुद्दे पर विधायक लेप्चा के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा मुख्य रूप से विदेशों में रहने वाले सिक्किमी लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने हेतु राज्य सरकार शीघ्र ही फॉरेन वर्कर्स ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट इंस्टीट्यूट चालू कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इसकी स्थापना भारत में मौजूद विभिन्न देशों के एम्बेसियों तथा इस कार्य में लगे अंतरराष्ट्रीय रोजगार नियुक्ति एजंसियों के माध्यम से होगी।

वहीं राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग तथा बुनियादी विकास निगम (एनएचआईडीसीएल) की परियोजनाओं की स्थिति के सम्बंधम में विधायक लेप्चा के सवाल पर मुख्यमंत्री ने बताया कि एनएचआईडीसीएल केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आता है और इसका रखरखाव, प्रबंधन तथा विकास केंद्र सरकार ही कर सकती है।

इसी तरह विधायक श्रीमती सुनीता गजमेर द्वारा सिक्किमी विद्यार्थियों के लिये आरक्षित मेडिकल सीटों के बारे में पूछे गये प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित चिकित्सा विज्ञान के सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट में सिक्किमी विद्यार्थियों के लिए 50 नि:शुल्क सीटें अनुमोदित की हैं। ये सीटें एनईईटी उत्तीर्ण जरूरतमंत विद्यार्थियों को आवंटित की जायेंगी।

वहीं विधायक पिन्सो नामग्याल लेप्चा द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के सम्बंध में पूछे गये सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर शीघ्र कदम उठाया जायेगा। सदन में अपने समापन भाषण में मुख्यमंत्री ने कार्यवाही में सक्रियता से भाग लेने हेतु सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया और यह आश्वस्त कराया कि राज्य सरकार राज्यवासियों को सभी केंद्रीय तथा राज्य सरकारी सुविधाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचायेगी।

इस अवसर पर वित्तीय चर्चा के दौरान विभिन्न मंत्रियों के प्रभार के तहत चर्चा हेतु पृथक अनुदान मांगें पेश की गयीं। उसके बाद मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) ने सदन में सिक्किम एप्रोप्रिएशन बिल, 2022 पेश किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। तत्पश्चात सदन ने वार्षिक आम बजट 2022-23 को भी पारित कर दिया।

अपनी प्रतिभा को पहचानें नौजवान : राज्यपाल

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 31 मार्च । राज्यपाल गंगा प्रसाद आज नेहरू युवा केंद्र संगठन, सिक्किम द्वारा आयोजित कार्यक्रम नेबरहूड यूथ पार्लियामेंट एवं एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, सामदोंग में उपस्थित रहे।

युवा शक्ति को सम्बोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि युवाओं में कार्य करने की अपार शक्ति होती है। नौजवान जो चाहे परिवर्तन ला सकता है। उन्हें अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लक्ष्य दुर्लभ जरूर है मगर असंभव नहीं है, अथक प्रयासों द्वारा ही लक्ष्य प्राप्ति होती है।

राज्यपाल ने अभिवावक एवं शिक्षकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि जब छात्र स्कूल में दाखिल होते हैं तो गीली मिट्टी के सामान होते हैं, उसे जिस प्रकार चाहे ढाला जा सकता है, अत: यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि छात्र को अनुशासन में रखते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करें।

नेहरू युवा केंद्र की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि यह संगठन नौजवानों को प्रेरित करता है एवं प्रतिभा से भरता है।

उन्होंने प्रधानमंत्री सरकारी योजनाओं जैसे खेलो इंडिया, आत्मनिर्भर भारत आदि का भी विस्तार किया। इस अवसर पर उन्होंने विकास स्वरूप सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, सामदोंग को 2,50,000 रुपये की राशि का अनुदान दिया साथ ही नेहरू युवा केंद्र के जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय युवाओं को सम्मानित भी किया।

इस समारोह में क्षेत्र प्रभारी, नेहरू युवा केंद्र, सिक्किम, की निदेशक एवं सदस्य, गंगटोक एसडीएम, रांगपो एसडीपीओ, विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षक, अधिकारी, पंचायत, ग्रामवासी एवं स्कूली बच्चे उपस्थित रहे।

पूर्व सरकार की रिपोर्ट की वजह से 17वें कर्मापा नहीं आ सके सिक्किम : गोले

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 31 मार्च । सीएम प्रेम सिंह तमांग (गोले) ने कहा कि 17वें कर्मापा उगेन थिनले दोरजी के इतने वर्ष तक सिक्किम न आ पाने की सबसे बड़ी वजह पूर्व की एसडीएफ सरकार का केन्द्र सरकार को भेजी गई रिपोर्ट है। राज्यपाल के बजेट अभिभाषण पर चर्चा में सहभागी विधायक सोनाम वेंचुग्पा के प्रश्न के जवाब में मुख्यमन्त्री ने यह बात कही। विधायक वेंचुंग्पा ने कर्मापा के सिक्किम आगमन में देरी को लेकर सवाल किया था।

सीएम गोले ने कहा कि 1997 में एसडीएफ सरकार में तत्कालीन मुख्य सचिव केएस राव ने 17वें कर्मापा उगेन थिनले दोरजी को चीन की गोटी की संज्ञा देते हुए केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने सिक्किम के साथ ही कुछ सीमावर्ती राज्यों में कर्मापा के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। पूर्व सरकार ने यदि इस प्रकार की रिपोर्ट भारत सरकार को नहीं भेजी होती तो 17वें कर्मापा उगेन थिनले दोरजी सिक्किम आ चुके होते।

इसके अतिरिक्त, सीएम गोले ने कहा कि मार्च 2018 में केन्द्र सरकार ने कर्मापा पर लगाए गए प्रतिबन्ध हटा लिए थे, उस समय की सरकार ने चाहा होता तो कर्मापा को सिक्किम लाया जा सकता था। लेकिन तत्कालीन सरकार ने किसी प्रकार की पहल नहीं की। इसके बाद, कर्मापा ने भारत छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर 17वें कर्मापा उगेन थिनले दोरजी इस समय भारत में होते तो वर्तमान राज्य सरकार उन्हें अवश्य सिक्किम लेकर आती।

सीएम गोले ने बताया कि कर्मापा वर्तमान में विदेश में हैं इसके बावजूद वर्तमान सरकार उन्हें सिक्किम लाने की भरपूर कोशिश कर रही है। मुख्यमन्त्री ने मन्त्री सोनाम लामा की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किए जाने और कर्मापा के स्वागत के लिए बजट में एक करोड़ रुपए के आवंटन किए जाने की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गत वर्ष कोरोना महामारी के कारण विदेश यात्रा नहीं की जा सकती लेकिन सरकार इस दिशा में पहल करेगी।

एसकेएम के घमंड और दादागिरी ने बीजेपी को पैरों तले रौंद दिया है : गोपाल छेत्री

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 31 मार्च । हाल ही में राजधानी गंगटोक में सत्ताधारी एसकेएम तथा प्रमुख विपक्षी एसडीएफ के बीच हुए संघर्ष की घटना के बाद प्रदेश भाजपा द्वारा दिये गये बयान की सिक्किम प्रदेश कांग्रेस ने तीव्र आलोचना की है। इस सम्बंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष गोपाल छेत्री ने राज्य में एसकेएम-भाजपा की साझेदारी को तथाकथित गठबंधन करार देते हुए इस बयान को भाजपा की चापलूसी करार दिया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश भाजपा पर कई आरोप भी लगाये हैं।

विज्ञप्ति में छेत्री ने कहा है कि 32 सदस्यीय सिक्किम विधानसभा में 12 विधायकों के साथ सत्तारूढ़ एसकेएम पार्टी के साथ तथाकथित गठबंधन के नाम पर भाजपा द्वारा दिया गया यह बयान जनहित में नहीं बल्कि चापलूसी करने वाला है। उनके अनुसार यह साफ हो गया है कि अपनी पार्टी के बयान में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राजू गिरी डर कर कांग्रेस पार्टी का नाम तक नहीं ले सके।

गौरतलब है कि एसडीएफ और एसकेएम के बीच हुई झड़प के बाद कांग्रेस द्वारा जारी एक बयान के जवाब में भाजपा द्वारा प्रवक्ता राजू गिरी के नाम से जारी एक बयान में कहा गया कि भाजपा ने घटना के बारे में समय रहते सुझाव दिये थे और प्रशासन को सतर्क भी किया था। इस पर छेत्री ने कहा, एसकेएम सरकार प्रदेश भाजपा के किसी भी सुझाव को नहीं मानने वाली है। प्रदेश भाजपा को पता नहीं है कि एसकेएम के घमंड और दादागिरी ने भाजपा को पैरों तले रौंद दिया है।

प्रदेश कांग्रेस की विज्ञप्ति के अनुसार एसडीएफ अध्यक्ष और 25 वर्षों तक मुख्यमंत्री पद पर रहे पवन चामलिंग पर बार-बार हमला करने वाली एसकेएम पार्टी भाजपा नेताओं और विधायकों पर भी हमला कर सकती है। ऐसे में तथाकथित गठबंधन में शामिल भाजपा को चाहिये कि वह समय रहते बुद्धिमानी दिखाए। जब एसकेएम भाजपा के किसी भी सुझाव का पालन ही नहीं करती है, तो यह अफवाह फैलाना कि वह उसके साथ गठबंधन में है, शर्म की बात है।

वहीं प्रदेश कांग्रेस ने सवाल किया है कि लोकतंत्र की हत्या, विपक्षी पार्टी (शेष पृष्ठ ०३ पर)

जापान के राजदूत ने स्लोप प्रोटेक्शन कार्य परियोजना स्थल का किया दौरा

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 31 मार्च । भारत में जापान के राजदूत सातोशी सुजुकी ने आज मार्तम स्थित एनएच-10 के निर्माणाधीन स्लोप प्रोटेक्शन कार्य के पायलट परियोजना स्थल का दौरा किया। इस दौरान जापानी राजदूत के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी था जिसमें काउंसेलर एई गोंडा एवं केंतारो ओरिता, प्रथम सचिव इक्को वातानाबे और द्वितीय सचिव मारी सकाई शामिल रहे।

पहाड़ी क्षेत्र में राजमार्ग के क्षमता निर्माण का यह प्रोजेक्ट केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर एनएचआईडीसीएल, पीएमयू-रानीपुल द्वारा तैयार किया जा रहा है। परियोजना स्थल पर जापानी दल का महाप्रबंधक (पी) शंकर भौमिक, प्रबंधक (पी) शेख फारूक, अभियंता अंकित मिश्रा तथा दीनेश कुमार जायसवाल ने स्वागत किया। वहां आगत प्रतिनिधियों के समक्ष परियोजना के जारी के सम्बंध में एक प्रोजेक्ट प्रजेंटेशन के साथ ही फील्ड गतिविधियों के बारे में भी विस्तार से बताया गया।

गौरतलब है कि उक्त परियोजना का कार्य मैसर्स केसीसी बिल्डकॉन प्रा. लि. तथा ऑथरिटी इंजीनियर मैसर्स एईसीओएम द्वारा किया जा रहा है। वहीं जेआईसीए ने परियोजना हेतु टोपोग्राफिक, ज्योग्राफिकल समेत सभी आवश्यक सर्वेक्षण तथा भू-तकनीकी जांच का काम सम्पन्न किया, जिसके माध्यम से निर्माण स्थल पर विभिन्न प्रकार के सम्बंधित कार्यों को सफलतापूर्वक किया जा सके।

दौरे के तहत जेआईसीए प्रतिनिधि दल का प्रतिनिधित्व मुख्य प्रतिनिधि सैतो मित्सुनोरी, मुख्य विकास वैज्ञानिक विनीत एस सरीन तथा सुश्री वातानाबे एरिसा ने किया। प्रतिनिधियों ने निर्माण का दौरा करने के बाद एनएचआईडीसीएल इंजीनियरों के (शेष पृष्ठ ०३ पर)

बजट पूर्व सरकार की नकल : कृष्ण खरेल

एसडीएफ ने लगाया पार्टी अध्यक्ष की आवाज को विधानसभा में दबाने का आरोप

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 31 मार्च । सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) पार्टी ने हाल ही में विधानसभा परिसर में अपने अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग पर हुए हमले के सिलसिले में न्याय की मांग की है। साथ ही एसडीएफ पार्टी ने राज्य की मौजूदा सरकार द्वारा पेश किये गये बजट को पूर्व सरकार की नकल करार देते हुए उसमें कुछ नया नहीं होने, बजट भाषण में मुख्यमंत्री पीएस गोले द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत हमला करने और विधानसभा में अपने अध्यक्ष की आवाज दबाने का भी आरोप लगाया है।

एसडीएफ के प्रचार मामलों के उपाध्यक्ष कृष्ण खरेल ने इस सम्बंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि एसडीएफ पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री अपने ऊपर हुए हमले के विरोध में तथा न्याय की मांग के साथ आज विधानसभा में उपस्थित हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष से न्याय की मांग करते हुए विधानसभा में सीएम गोले द्वारा दिये गये बजट भाषण के उन असंसदीय हिस्सों को हटाने की मांग की है, जिनमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत हमला बोला है।

विज्ञप्ति के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि मैं आज विरोध के साथ सदन में उपस्थित हुआ हूं। इसका कारण यह है कि अभी तक विधानसभा परिसर में हुए हमले के दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिन व्यक्तियों ने मुझे गाली दी तथा मेरे खिलाफ अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया, वह सदन की विजिटर्स गैलरी में बैठे थे। उन्होंने कहा, सदन की मर्यादा का पालन सुनिश्चित करना माननीय अध्यक्ष का प्रमुख दायित्व बनता है। इसके लिये उन्होंने कई धाराओं का भी जिक्र किया।

वहीं विज्ञप्ति में एसडीएफ ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही में हमारे अध्यक्ष को बोलने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। एसकेएम पार्टी का यही एकमात्र एजेंडा है कि पूर्व मुख्यमंत्री को किसी भी मुद्दे पर अपनी आवाज उठाने का मौका नहीं प्राप्त हो सके। यह लोकतंत्र पर हमला है और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।

एसडीएफ उपाध्यक्ष (प्रचार मामला) कृष्ण खरेल ने प्रश्न पूछते हुए कहा कि मौजूदा राज्य सरकार क्यों एक व्यक्ति से इतनी डर रही है? सरकार जनता की आवाज क्यों सुनना नहीं (शेष पृष्ठ ०३ पर)

दूधिचुआ की बेटी ने सिंगरौली जिले का नाम किया रौशन

गणेश सिंह 'विशाल'

सिंगरौली, 31 मार्च । काशी विद्यापीठ वाराणसी के सभागार में हीरालाल मिश्र (मधुकर) द्वारा संपादित 'नयी सदी के स्वर' भाग-2 काव्य का संग्रह का विमोचन विगत दिनों किया गया। इस काव्य संग्रह में 140 कवियों एवं कवित्रीयों की रचनाओं को संकलित किया गया।

इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, वंगकुरु, हैदराबाद, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के सम्मानित एवं ख्याति प्राप्त कवि एवं कवयित्री उपस्थित थे।

इन 140 कवि एवं कवित्रियों में से मात्र 39 को विश्व हिंदी शोध एवं संवर्धन अकादमी वाराणसी द्वारा स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसमें दूधिचुआ की नवोदित कवयित्री सुश्री सुरभि सिंह पुत्री श्री डीके सिंह शिक्षक डीएवी स्कूल दूधिचुआ को भी स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

विदित हो कि सुश्री सुरभि सिंह अपने दादा एवं अपने पिता के गुरु श्री इंदु भूषण कोचगवे से प्रेरणा पाकर कविता लेखन के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में वह हैदराबाद के प्रतिष्ठित आईटी सेक्टर में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है कार्यक्षेत्र में से समय निकालकर उन्होंने कविता लेखन का कार्य जारी रखा तथा अपने सिंगरौली जिले का नाम रोशन कर सम्मान बढ़ाया है।

टीटीपी ने की रमजान के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ नए हमले का ऐलान

इस्लामाबाद, 31 मार्च (एजेन्सी)। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर पूरी ताकत से हमला करने के लिए आतंकी हमलों की एक नई लहर तैयार है क्योंकि पाकिस्तानी तालिबान ने रमजान के पवित्र इस्लामिक महीने के दौरान अपने आक्रामक 'अल-बद्र' की शुरुआत करने का ऐलान किया है।

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के प्रवक्ता मोहम्मद खुरासानी ने एक बयान में कहा, 'वसंत आक्रमण मुस्लिम पवित्र महीने रमजान के पहले दिन से शुरू होगा और सुरक्षा बलों और उनके सहयोगियों को निशाना बनाएगा।'

उन्होंने कहा, 'इस मिशन में शहादत (आत्मघाती) ऑपरेशन, घात हमले, माइन ऑपरेशन, काउंटर अटैक, टारगेट अटैक, लेजर और स्नाइपर ऑपरेशन शामिल होंगे।'

हाल ही में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ टीटीपी आतंकवादियों द्वारा आतंकवादी हमलों में वृद्धि के मद्देनजर एक नए हमले का आह्वान किया गया है।

हाल ही में, खैबर पख्तूनख्वा (केपी) प्रांत के टैंक जिले में एक फ्रंटियर कॉर्प्स (एफसी) किले पर लक्षित एक बड़े हमले के दौरान कम से कम छह पाकिस्तानी सैनिकों ने शहादत को गले लगा लिया था।

यह हमला राजधानी इस्लामाबाद और टैंक जिले के आसपास के इलाकों को निशाना बनाने के लिए योजनाबद्ध एक बहुत बड़े हमले की एक श्रृंखला का हिस्सा था।

पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 28 और 29 मार्च को इस्लामाबाद के शकरपरियान इलाके से कम से कम चार टीटीपी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, जबकि चार और आतंकवादियों को टैंक जिले से जुड़े और दक्षिण वजीरिस्तान क्षेत्र के करीब एक महत्वपूर्ण क्षेत्र लक्की मारवात से गिरफ्तार किया गया था।

तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से टीटीपी ने पाकिस्तान में अपने हमले तेज कर दिए हैं। इसे अफगान तालिबान का एक छत्र संगठन माना जाता है और यह अफगान तालिबान के निर्देशों के अनुरूप पाकिस्तान में काम कर रहा है।

यह उल्लेख करना उचित है कि अफगान तालिबान ने पिछले साल पाकिस्तान और टीटीपी के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान की थी, जिसके परिणामस्वरूप एक महीने का संघर्ष विराम समझौता हुआ था। हालांकि, टीटीपी द्वारा पाकिस्तान पर समझौते की शर्तो का पालन नहीं करने का आरोप लगाने के बाद समझौता टूट गया।

यह बताया गया है कि टीटीपी ने पाकिस्तान से अपने आतंकवादियों को पाकिस्तान लौटने की अनुमति देने की मांग की है, खासकर जब अफगान तालिबान ने विदेशी लड़ाकों को अपने-अपने देशों में लौटने और अफगानिस्तान छोड़ने का निर्देश दिया था।

हाल ही में अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुसने के प्रयास किए गए हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है, जो टीटीपी आतंकवादियों के साथ घातक संघर्ष में शामिल हैं।

टीटीपी ने पाकिस्तान में कई हमलों का दावा किया है, जिसमें दर्जनों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। टीटीपी की रमजान में आक्रामक की घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब प्रधानमंत्री इमरान खान को विपक्षी दलों द्वारा एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में मतदान के लिए अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उन्हें हटाना चाहते हैं।

भ्रष्टाचारियों पर सीएम योगी का एक्शन, सोनभद्र डीएम और गाजियाबाद एसएसपी सस्पेंड

लखनऊ, 31 मार्च (एजेन्सी)। सीएम पद की शपथ लेने के तुरंत बाद एक्शन में आए सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई का असर दिखने लगा है। यूपी में भ्रष्टाचार को लेकर घिरे अधिकारियों पर योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को सीएम योगी ने एक आईएएस और एक आईपीएस अफसर को सस्पेंड कर दिया है। दोनों अफसरों पर भ्रटाचार के आरोप लगे हैं। दोनों अफसरों की शिकायतें विधानसभा चुनाव से पहले भी हो चुकी हैं। सीएम योगी की इस कार्रवाई से यूपी के अन्य अफसरों में हड़कंप मचा है।

यूपी के लापरवाह और आपराधिक प्रवृत्ति वाले अफसरों के खिलाफ सीएम योगी एक्शन में आ गए हैं। गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार और अन्य आपराधिक मामलों के दोस्ती दो अफसरों पर गाज गिरा दी है। सीएम योगी ने सोनभद्र के डीएम टीके शिबू और गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने गुरुवार को बताया कि यूपी सरकार ने सोनभद्र के जिलाधिकारी टी के शिबू और एसएसपी गाजियाबाद पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने बताया कि दोनों अफसरों पर जनता से जुड़े कार्यों में कथित लापरवाही बरतने और अपराध नियंत्रण नहीं कर पाने के आरोप लगे थे। सोनभद्र डीएम टीके शिबू पर के खिलाफ विधानसभा चुनाव से पहले भी लापरवाही के आरोप लग चुके हैं।

यूपी में दो अफसरों के सस्पेंशन के बाद अन्य विभाग के अफसरों में हड़कंप मचा है। अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी द्वारा जारी सस्पेंड आदेश में कहा गया है कि शिबू के विरुद्ध खनन, जिला खनिज न्यास समिति तथा अन्य निर्माण कार्यों में जनप्रतिनिधियों द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायतें से संबंधित तथ्य शासन के संज्ञान में आए हैं। इसके अलावा हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भी शिबू द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में गंभीर लापरवाही बरतने का भी मामला सामने आया था। इन शिकायतों की, मिर्जापुर मंडल के आयुक्त द्वारा की गयी जांच में शिबू को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के आधार पर शासन ने उन्हें सस्पेंड किया गया है। निलंबन आदेश में कहा गया है कि शिबू के उक्त कृत्य अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली 1968 के नियम 3 का उल्लंघन हैं। अत: इन तथ्य एवं परिस्थितियों पर सम्यक विचार करते हुए राज्यपाल ने शिबू को निलंबित कर उक्त नियमावली के तहत उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए हैं। इसके तहत शुरू की जाने वाली विभागीय कार्रवाई के लिए वाराणसी मंडल के आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। निलंबन की अवधि में शिबू को लखनऊ स्थित कार्यालय, राजस्व परिषद से संबद्ध रहने और बिना लिखित अनुमति प्राप्त किये राज्य मुख्यालय नहीं छोड़ने को कहा गया है।

सोनिया गांधी ने मनरेगा के बजट में कटौती का विषय लोकसभा में उठाया, सरकार ने आरोपों का खंडन किया

नई दिल्ली, 31 मार्च (एजेन्सी)। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरूवार को लोकसभा में कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के बजट में कटौती की गई है जिसके कारण मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में सरकार को पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित करना चाहिए।

सोनिया गांधी ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया।

सरकार ने उनके आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मनरेगा के लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन हुआ है, जबकि पूर्व की संप्रग सरकार के समय न सिर्फ आवंटन कम था, बल्कि भ्रष्टाचार भी होता था।

शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए सोनिया गांधी ने कहा, मनरेगा का कुछ साल पहले कुछ लोगों ने मजाक बनाया था । हालांकि उसी मनरेगा ने कोविड और लॉकडाउन के दौरान प्रभावित परिवारों की सहायता की। फिर भी मनरेगा के लिए आवंटित बजट में कटौती की जा रही है।

उन्होंने दावा किया कि बजट में कटौती के कारण मजदूरों को काम और मजदूरी मिलने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा, इस साल मनरेगा का बजट पिछले साल के मुकाबले 35 प्रतिशत कम है। इससे मजदूरों के भुगतान में देरी होती है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करती हि मनरेगा के लिए उचित आवंटन हो, काम के 15 दिनों के भीतर कामगारों को मजूदरी का भुगतान हो तथा भुगतान में देरी पर मुआवजे भी दिया जाए।

इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, वह (सोनिया) देश की एक वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने सदन में जो विषय रखा है वो पूर्ण रूप से तथ्यों से परे है। साल 2013-14 में (संप्रग सरकार के समय) मनरेगा का 33 हजार करोड़ रुपये का बजट था, जो आज एक लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, संप्रग के समय आवंटित बजट खर्च नहीं होता था। लेकिन मोदी सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया। इनके (कांग्रेस) समय सिर्फ भ्रष्टाचार होता था।

इस दौरान कांग्रेस सदस्य हंगामा करने लगे।

इस पर ठाकुर ने कहा, ये लोग मंत्री की ओर से जवाब देने का विरोध कर रह है। यह दिखाता है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति करता है।

बाद में पीठासीन सभापति रमा देवी ने व्यवस्था देते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने शून्यकाल में जो विषय उठाये हैं, सरकार उसका उत्तर देना चाहे, तो दे सकती है ।

रेप के आरोपियों संग थाने में पुलिसकर्मियों ने मनाई होली, गहलोत बोले- होगी कार्रवाई

जयपुर, 31 मार्च (एजेन्सी)। राजस्थान के धौलपुर- दौस एसपी का तबादला करने के बाद सीएम गहलोत ऐक्शन मोड पर है। सीएम अशोक गहलोत ने हनुमानगढ़ जिले के पल्लू थाने में दुष्कर्म के आरोपियों संग डीजे पर थिरके पुलिस कर्मियों पर एसपी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। सीएम गहलोत ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। बुधवार को सीएम गहलोत ने धौलपुर-दौसा के एसपी बदल दिए थे। सीएम गहलोत ने लगातार दूसरे दिन आज भी सभी रेंज आईजी- एसपी के साथ बैठक कर कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा की। उल्लेखनीय है कि हनुमानगढ़ जिले के पल्लू थाना प्रभारी अमर सिंह सहित अन्य पुलिस कर्मियों का दुष्कर्म के प्रयास के आरोपियों संग होली मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आरोपियों पर पल्लू थाने में ही मामला दर्ज हुआ था।

सीएम गहलोत ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। सीएम गहलोत ने पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कहा कि ऐसी घटनाओं से आरोपियों को हौंसले बुंलद होते हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि कानून के राज से समझौता नहीं करेंगे कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। पुलिस इसी भावना को ध्यान में रखकर हर मामले में निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करें। पीड़ित को न्याय दिलवाना पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त योग्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि सीएम गहलोत ने बुधवार के पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली थी। बैठक के बाद धौलपुर और करौली एसपी के तबादले करने के आदेश जारी कर दिए गए। धौलपुर में कांग्रेस विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा पर बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ मारपीट का आरोप है। पुलिस विधायक पर केस भी दर्ज कर लिया गया। दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा के सुसाइड मामले में एसपी अनिल कुमार का तबादला कर दिया। जबकि लालसोठ एसएचओ को निलंबित कर दिया था।

थाने में रेप के आरोपियों के साथ होली मनाने का वीडियो 25 मार्च को वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में पल्लू थानाधिकारी अमर सिंह, आरोपी राजू ढूकिया व गोपीराम नाई के साथ स्टाफ सहित थाने में ही होली खेलते नजर आ रहे हैं। आरोपियों पर 4 मार्च 2022 को पल्लू थाने में ही मामला दर्ज हुआ था। राजू ढूकिया व गोपीराम नाई पर पल्लू थाने में इस्तगासे के जरिए पल्लू के ही एक गांव की महिला ने 4 मार्च को दुष्कर्म के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। इस पर पुलिस ने नामजद राजू ढुकिया व गोपीराम नाई पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय पल्लू पुलिस उनके साथ होली खेलती नजर आई।

आज से महंगा हो जाएगा बुखार-खांसी और दर्द का इलाज, दवाओं की कीमत जेब पर बढ़ाएगी बोझ

राजेश अलख

नई दिल्ली, 31 मार्च । पहले से ही कीमतों में वृद्धि से जूझ रहे उपभोक्ताओं को अब अपने घरेलू बजट में दवा की ऊंची कीमतों को भी ध्यान में रखना होगा। दरअसल कल से यानी 1 अप्रैल से कई आवश्यक दवाओं की कीमतें बढ़ने जा रही हैं।

आवश्यक दवाएं जैसे, दर्द निवारक, एंटी-इनफेक्टिव, कार्डियक और एंटीबायोटिक्स आदि 1 अप्रैल से महंगी हो जाएंगी क्योंकि सरकार ने दवा कंपनियों को वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक में बदलाव के अनुरूप वृद्धि की अनुमति दे दी है। नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी ने 800 से अधिक जरूरी दवाओं की कीमतों में करीब 11 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया।

जिन दवाओं के दाम बढाए गए हैं, उन्हें आवश्यक दवाइयों की श्रेणी में गिना जाता है और ये नेशनल एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन में आती हैं। ये दवाएं हैं- एंटीबायोटिक्स, सर्दी-खांसी की दवाएं, एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, कान-नाक और गले की दवाएं, एंटीसेप्टिक्स, पेन किलर, गैस की दवाएं और एंटीफंगल दवाएं। करीब 800 से ज्यादा दवाएं हैं दो महंगी होंगी। इन दवाओं के दाम अब 1 अप्रैल से 10.76 फीसदी तक बढ़ जाएंगे।

बुखार के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली पैरासिटामोल भी महंगी होगी। पैरासिटामोल और बैक्टीरियल इंफेक्शन के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एजिथ्रोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक्स, फोलिक एसिड जैसे एंटी एनेमिक प्रिसप्रिक्पशन, विटामिन और मिनरल्स भी शामिल हैं जिनके दाम बढ़ेंगे।

दवाओं की कीमतों के बढ़ने के पीछे थोक महंगाई को मुख्य वजह बताया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, थोक महंगाई पर आधारित होलसेल प्राइस इंडेक्स (डब्ल्यूपीआई) में 2021 में एक साल पहले की तुलना में 10.76 फीसदी का बदलाव आया है।

ऐतिहासिक रूप से, डब्ल्यूपीआई में वार्षिक परिवर्तन के कारण कीमतों में वृद्धि पिछले कुछ वर्षों में - 1-2 प्रतिशत की सीमा में - मामूली रही है। 2019 के लिए, एनपीपीए ने दवा कंपनियों को लगभग 2 प्रतिशत की कीमतों में वृद्धि की अनुमति दी थी, जबकि 2020 में वार्षिक डब्ल्यूपीआई में बदलाव के अनुरूप कीमतों में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। लेकिन ये पहली बार है जब कीमतें 10 प्रतिशत तक बढ़ाई जा रही हैं।

कीमतों में भारी बढ़ोतरी को तार्किक रूप से सही ठहराया जा रहा है लेकिन इससे लोगों को खासी समस्या हो सकती है। एक साथ इतनी बढ़ोत्तरी लोगों को परेशान कर सकती है। यह घटनाक्रम उद्योग के लिए स्वागत योग्य खबर है, जो कई कारकों के कारण विनिर्माण लागत में वृद्धि से जूझ रहा है। महामारी के दौरान, उद्योग कच्चे माल (सक्रिय दवा सामग्री, या एपीआई), माल और प्लास्टिक और पैकेजिंग सामग्री की कीमतों में वृद्धि से प्रभावित हुआ था। कार्डियो-वैस्कुलर, डायबिटीज, एंटीबायोटिक्स, एंटी-इंफेक्टिव और विटामिन को बनाने के लिए अधिकांश फार्मा सामग्री चीन से आयात किए जाते हैं, जबकि कुछ कच्चे माल (एपीआई) के लिए, चीन पर निर्भरता 80-90 प्रतिशत है। एक बार जब चीन में 2020 में महामारी फैल गई, तो व्यापक पैमाने पर आपूर्ति में व्यवधान और कमी हुई, जिससे घरेलू कंपनियों के लिए उच्च लागत आई।

दिल्ली में मास्क न लगाने पर अब जुर्माना नहीं

राजेश अलख

नई दिल्ली, 31 मार्च । दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने लोगों को राहत देते हुए मास्क न लगाने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान समाप्त कर दिया है। हालांकि इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी होगा।

बृहस्पतिवार को उप-राज्यपाल अनिल बैजल से वीडियो कॉफ्रेंसिंग पर संबंधित विभागों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव, एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया, एनसीडीसी के डॉ. एसके सिंह समेत अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में कोरोना के मामलों पर चर्चा करते हुए कहा गया है कि संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया है।

डीडीएमए के कोरोना की गाइड लाइंस में छूट देते हुए दिल्ली के लोगों को और राहत दे दी है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि टेस्टिंग, ट्रेकिंग और वैक्सीन को बढ़ावा देना है और लोगों से अपील की है कि वह सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बचाव जारी रखें। हालांकि सूत्रों का कहना है कि डीडीएमए जारी आदेश में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने की पाबंदी जारी रख सकती है। फिलहाल संक्रमण की घटते प्रभाव को देखते हुए यह निर्णय लिए गए हैं। इसके अलावा बाकी प्रतिबंध डीडीएमए पहले ही हटा चुका है।

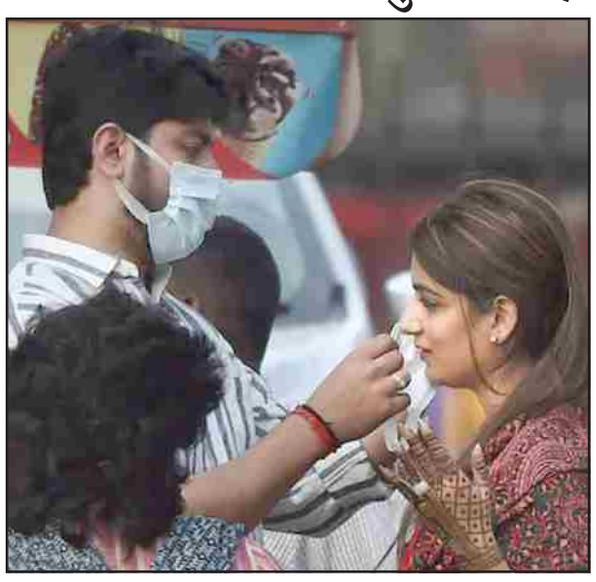

केंद्र सरकार देशव्यापी स्तर पर कोरोना के संक्रमण और मृत्युदर में कमी के मध्य कोविड प्रोटोकॉल के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।

केंद्र सरकार ने 31 मार्च से तमाम तरह के कोविड प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। हालांकि फेस मास्क और दो गज की दूरी का नियम अभी बरकरार रहेगा और लोगों को फेसमास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। केंद्रीय गृहमंत्रालय ने करीब दो साल बाद, 31 मार्च से कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में हाल ही में कहा कि पिछले 24 महीनों में वैश्विक महामारी के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं जैसे बीमारी का पता लगाने के लिए टेस्टिंग, निगरानी, संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, उपचार, टीकाकरण, अस्पताल के बुनियादी ढांचे के विकास आदि के संबंध में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि साथ ही, अब आम जनता भी कोविड-19 से निपटने के लिए आवश्यक उचित व्यवहार को लेकर काफी जागरूक है।

यूक्रेन में अभी भी फंसे हैं 50 भारतीय, कुछ ही लौटने को तैयार; सरकार ने राज्यसभा को बताया

नई दिल्ली, 31 मार्च (एजेन्सी)। लगभग 50 भारतीय अभी भी यूक्रेन में हैं और उनमें से कुछ ही लौटने को तैयार हैं। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज राज्यसभा को बताया कि उनकी वापसी की सुविधा दूतावास द्वारा दी जा रही है। मंत्री ने कहा कि पिछले महीने से 22,500 भारतीय युद्धग्रस्त देश से लौटे हैं।

रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान केंद्र सरकार ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की थी, जो यूक्रेनी सीमाओं पर देशों तक पहुंचने में कामयाब रहे, जिसमें वायु सेना की भी मदद रही। यह पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने संकट के बीच भारतीयों को स्वदेश भेजा है।

जब 2020 में कोरोनोवायरस महामारी की चपेट में आया, तो केंद्र ने भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया और भारत और 35 अन्य देशों के बीच यात्रा की सुविधा के लिए एयर बबल बनाए थे। एयर बबल व्यवस्था दो देशों के बीच एक अस्थायी समझौता था जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करना था जब कोविड -19 महामारी के कारण नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें निलंबित कर दी गई थीं।

विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी ने राज्यसभा में जानकारी दी कि वंदे भारत मिशन और एयर बबल अरेंजमेंट के तहत अब तक संचालित उड़ानों में लगभग 2.97 करोड़ यात्रियों को सुविधा दी गई है। तालिबान के सत्ता में आने पर अफगानिस्तान से भारतीयों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किए गए सशस्त्र बलों के ऑपरेशन देवी शक्ति ने 669 लोगों को निकाला।

इनमें 448 भारतीय नागरिक, 206 अफगान (हिंदू सिख अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों सहित) और अन्य राष्ट्रीयताओं के 15 लोग (नेपाल, लेबनान और युगांडा) सात उड़ानों (छह 16 से 25 अगस्त, 2021 के बीच संचालित और अंतिम 10 दिसंबर को शामिल थे) शामिल थे।

'हारे हैं मरे नहीं, यह पंजाब के अस्तित्व की लड़ाई', आप पर भड़के नवजोत सिंह सिद्धू

नई दिल्ली, 31 मार्च (एजेन्सी)। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से अपने ही अंदाज में आ गए हैं। विधानसभा चुनाव में खुद अमृतसर पूर्व सीट से चुनाव हारने के बाद से कुछ दिन वह शांत थे, लेकिन अब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे हैं। गुरुवार को वह पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की महंगाई के विरोध में आयोजित प्रदर्शन में भी शामिल हुए। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस दौरान आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है।

उन्होंने कहा कि यह नई सरकार पंजाब की रूह का समझौता कर रही है। राज्यसभा में बाहरी लोगों को भेजने का भी सिद्धू ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया।

नवजोत सिंह सिद्धू ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'चंडीगढ़ पंजाब के हाथ से चला गया है। वहां अब अफसरों की नियुक्ति कोई और ही कर रहा है। यहां एक नई सरकार आई है, वो सांसदों के सौदे कर रही है। और लोगों की तो बात ही छोड़ो, ये लोग तो सांसदों की ही बोली लगा रहे हैं।' उन्होंने कहा कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं, वह पंजाब के रूह की जंग है।

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, 'यह पंजाब के रूह की लड़ाई है। मैं बगराड़ी भी पंजाब की रूह के लिए लड़ने को ही गया था। मुझे बताओ कि क्या यह शहीद भगंत सिंह और भीमराव आंबेडकर की विचारधारा से समझौता नहीं हो रहा है। यह आंदोलन पंजाब की रूह का आंदोलन है। यह पंजाब के अस्तित्व की लड़ाई है, ये जीतने भी विधायक यहां खड़े हैं, हार गए हैं, लेकिन मरे नहीं हैं।'

गौरतलब है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से खुद को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के दो दर्जन नेताओं को बुलाकर भी उन्होंने मीटिंग की थी और इस बात के संकेत दिए थे कि पंजाब कांग्रेस की कमान उन्हें ही सौंपा जाए।

जापान के राजदूत .....

साथ तकनीकी विचार साझा किये। इस कार्य की शुरुआत के बाद से इसकी अग्रगति को देखते हुए जेआईसीए दल ने रिकॉर्ड अंतराल के बाद यह दौरा किया है।

उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष मई तक इस निर्माण कार्य के पूरा होने की सम्भावना है। बहरहाल परियोजना का 60-70 फीसदी कार्य सम्पन्न किया जा चुका है। वर्तमान में एनएच-10 पर गैधारा तथा मार्तम में दो जगहों पर एनएचआईडीसीएल द्वारा कार्य किये जा रहे हैं। जापानी राजदूत सुजुकी ने कार्य की प्रगति की प्रशंसा की और एनएचआईडीसीएल के इंजीनियरों, मैसर्स केसीसी बिल्डकॉन प्रा. लि., मैसर्स एईसीओएम तथा अन्य लोगों को इसके लिये शुभकामनाएं दी।

बजट पूर्व सरकार .....

चाहती, जो हमारे अध्यक्ष सदन में रखना चाहते हैं? उन्होंने आगे कहा कि सत्ताधारी मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री का बजट भाषण महज पूर्व सरकार की ही कॉपी है। अपने बजट भाषण पर चर्चा हेतु दिये गये तीन घंटे के भाषण में मुख्यमंत्री ने इससे सम्बंधित कुछ नहीं कहा, बल्कि हमारे अध्यक्ष पर व्यक्तिगत हमला ही किया है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष भी मूकदर्शक बने रहे। वहीं राज्यपाल के भाषण का जवाब देने हेतु एसडीएफ अध्यक्ष को केवल सात मिनट दिये गये, जिसके दौरान भी अरुण उप्रेती, सोनम लामा और स्वयं पीएस गोले ने रुकावट उत्पन्न की।

वहीं बजट के बारे में बोलते हुए विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसमें मुख्य रूप से बड़ी परियोजनाओं के लिये धनराशि मंजूर की गयी है, जबकि 100 से अधिक छोटी परियोजनाएं आवंटन की कमी झेल रही हैं। वहीं राज्य में महंगाई बढ़ने से जनता परेशान है और मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से अधिक हो गयी है। मोटे तौर पर राज्य बजट में कोई दिशा, कोई दूरदर्शिता नहीं है।

इसके साथ ही विज्ञप्ति में राज्य सरकार के बजट में कोविड के कारण शिक्षा क्षेत्र पर पडने वाले प्रभाव तथा गरीबी बढ़ने के बारे में कोई योजना नहीं होने की बात भी कही गयी है।

ऐसे में एसडीएफ पार्टी ने विधानसभा की कार्यवाही इस तरह करने की मांग की है, जिससे कि सिक्किम तथा यहां की जनता की आवाज, आशाएं तथा आकांक्षा को दबाया न जा सके। विज्ञप्ति के अनुसार एसडीएफ पार्टी सिक्किमी जनता की भलाई हेतु दिन-रात कार्य करने को प्रतिबद्ध है।

एसकेएम के घमंड .....

और उसके नेताओं पर बार-बार हमले और घोर अशांति के कारण एसडीएफ ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की है, तो उस पर प्रदेश भाजपा क्यों चुप है? इसे लेकर राजभवन की प्रतिक्रिया में भाजपा ने क्या किया? देश में पूर्ण बहुमत के साथ शासन करने वाली भाजपा एसकेएम की लोकतंत्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर सकी? आखिर भाजपा की क्या भूमिका है?

इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हाल ही में चार राज्यों के चुनाव जीत चुकी भाजपा अपने 10 विधायकों सहित 12 सदस्यों के साथ सिक्किम में पैर नहीं जमा पायी है। कायरता के साथ वह केवल एसकेएम की चमचागिरी कर रही है। जनता यह सभी कुछ देख रही है। दूसरे राज्यों में जीत हासिल कर खुश भाजपा को शायद यह पता नहीं है कि नेता की जीत हुई और जनता हार गई है। आज महंगाई ने विकराल रूप ले लिया है, जनता परेशान है, लेकिन भाजपा का यह कहना कि वह राज्य में गठबंधन सरकार में है, हास्यास्पद ही है।

प्रदेश कांग्रेस ने आगे सुझाव देते हुए कहा, यदि हिम्मत है तो प्रदेश भाजपा 12 विधायकों के साथ अपने पैरों पर खड़ा हो। सिक्किम के भविष्य और यहां के लोगों के हित में लोकतंत्र की रक्षा हेतु सरकार के गलत कार्यों का घोर प्रतिवाद करने में क्षमता रखनी होगी, लेकिन यह शर्म की बात है कि एक भी मंत्री पद हथिया न सकने वाली भाजपा का यह कहना कि वह गठबंधन सरकार में है। उनके अनुसार थोड़ी कोशिश कर ही राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में रहने वाली भाजपा द्वारा यह तथाकथित गठबंधन को ढोना, उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को ही दर्शाता है।

राज्यसभा में जाने को लेकर नीतीश कुमार ने साफ की स्थिति, बोले- व्यक्तिगत इच्छा नहीं

पटना, 31 मार्च (का.सं.)। राज्यसभा में जाने की इच्छा को लेकर पूछे गये सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। बुधवार को एक न्यूज चैनल से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा था कि वे तीन सदनों का सदस्य रह चुके हैं। सिर्फ राज्यसभा बाकी है। इसी संदर्भ को लेकर गुरुवार को विधानसभा के मुख्यमंत्री कक्ष में पत्रकारों ने उनसे उनकी इच्छा जाननी चाही।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राजनीति के शुरुआत में मैं क्षेत्रों में बहुत घूमा करता था। लोगों से मिलता रहता था। इसी दौरान मेरी एक ही इच्छा थी कि सांसद बनूं। वह मैं बन गया। इसके पहले विधायक भी मैं बना था। पुराना बाढ़ लोकसभा क्षेत्र में अपने पुराने साथियों से मुलाकात करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि काफी दिनों से इसके लिये कार्यक्रम बना रहा था। अपने पुराने साथियों-सहयोगियों से मिलना चाहता था, पर समय नहीं मिल पाता था। इसी बीच में कोरोना का दौर आया। अब जाकर पुराने साथियों और वहां के लोगों से मिल रहा हूं। कुछ और क्षेत्र बाकी हैं, जहां आगे जाऊंगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 16 सालों से बिहार के लोगों की सेवा कर रहा हूं। इन 16 सालों में मैंने राज्य के हर तबके और सभी क्षेत्रों के विकास के लिए काम किया। किसी भी क्षेत्र को मैंने छोड़ा नहीं है। सड़क, पुल-पुलिया का निर्माण हो या स्कूल-अस्पताल बनाना। सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कार्य हुए हैं।

वर्ष 2006 के पहले और अब की स्थिति में राज्य में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। यह साफ दिखता है। पहले और आज के पटना में काफी फर्क आया है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के 715 मामले दर्ज : जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली, 31 मार्च (एजेन्सी)। सीबीआई ने 2017 से 2021 तक 45 विभागों में केंद्र सरकार के 715 कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के 715 मामले दर्ज किए हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित जवाब में कहा, विभिन्न विभागों से संबंधित 1,281 कर्मचारियों पर रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच एजेंसी द्वारा मामला दर्ज किया गया था।

उन्होंने कहा कि अलग-अलग मामलों में संबंधित कैडर नियंत्रण प्राधिकरण (सीसीए) द्वारा संबंधित अनुशासनात्मक नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 2017 में 210, 2018 में 158, 2019 में 141, 2020 में 95 और 2021 में 111 मामले दर्ज किए गए।

भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत भ्रष्टाचार का सामना करने वाले लोक सेवकों के लिए देश में कड़े दंड कानून हैं।

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 बेनामी लेनदेन को प्रतिबंधित करता है। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 लोक सेवकों को धन शोधन के अपराध के लिए दंडित करता है।

भारत 2005 से भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता (अनुमोदित नहीं) भी है।

कई पूर्व मंत्री और नामी चेहरे खहते हैं आप में एंट्री, जम्मू-कश्मीर में पैर पसारने की तैयारी

जम्मू, 31 मार्च (एजेन्सी)। चार राज्यों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बीच आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब को अपने जादू में ले उड़ी। पंजाब में करिश्मा करने के बाद आप के कदम अन्य राज्यों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के बाद आप ने अपनी नजरें जम्मू कश्मीर की तरफ भी घुमा दी हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा के मुकाबले आप के लिए ज्यादा संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तारीखों से पहले आप से जुड़े नेता प्रदेश में पार्टी की गहरी पैठ बनाने की कोशिश में भी जुटे हैं।

चुनाव आयोग की घोषणा के बाद, आप ने जम्मू-कश्मीर की सभी 90 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। हिन्दुस्तान टाइम्स से बात करते हुए, आप के पर्यवेक्षक और जम्मू-कश्मीर के सह-प्रभारी सलाहुद्दीन खान का कहना है, हमारी नीति जम्मू-कश्मीर के लिए समान है और कुछ भी छिपा नहीं है। हमारी योजना जम्मू-कश्मीर की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की है और हमने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली और पंजाब की तरह, हम अपने सीमित संसाधनों के भीतर जम्मू-कश्मीर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन हम जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

खान ने कहा कि आप दोनों क्षेत्रों में रैलियां करेगी और चुनाव की घोषणा होते ही पूरी ताकत से जुट जाएगी। हम लोगों से जुड़ रहे हैं और हमें उनसे जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है। हमारा ख़ल्स पॉइंट यह है कि हमारे यहां कोई नकारात्मकता नहीं है। लोग हमारी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि पार्टी सही है और आप नेता भी। अब, हमें इस समर्थन को वोटों में बदलना है।

उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भाजपा के पास हिंदू-मुस्लिम और पहाड़ी-डोगरा के अलावा राजनीति की पेशकश करने के लिए कुछ भी नहीं है। जबकि हमारा एजेंडा आम लोगों के लिए बिजली है। हम दिल्ली और पंजाब में जितना दे रहे हैं, उससे ज्यादा देंगे। हम जम्मू-कश्मीर में भी दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करेंगे जैसे हमने पंजाब में किया था। आप पर्यवेक्षक ने कहा कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप को नेकां, पीडीपी, कांग्रेस और भाजपा की परवाह नहीं है।

सलाहुद्दीन खान का कहना है, वे जो कहते हैं, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हम अन्य दलों की नीति और कार्यक्रमों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हम लोगों के कल्याण के बारे में चिंतित हैं। चार चीजें हमारे ट्रेडमार्क हैं- स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, शिक्षा सुधार, बिजली और पानी। अरविंद केजरीवाल का सपना है कि लोगों को ये चार सुविधाएं मुफ्त में मिले क्योंकि ये आम आदमी के बजट को बिगाड़ती हैं।

उन्होंने बताया कि जब परिसीमन पैनल अपना काम पूरा कर लेगा और चुनाव आयोग की ओर से तारीखों की घोषणा हो जाएगी तो केजरीवाल और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेतृत्व जम्मू-कश्मीर में रैलियां करेंगे। हालांकि, खान ने कहा, जब तक भाजपा नहीं चाहती, तब तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव नहीं होंगे। अगर उन्हें लगता है कि वे मुश्किल में हैं तो चुनाव नहीं कराए जाएंगे।

यह पूछे जाने पर कि क्या पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों सहित राजनेता आप में शामिल होने के लिए संपर्क कर रहे हैं, उन्होंने कहा, हम उन सभी को आमंत्रित कर रहे हैं जिनकी छवि साफ-सुथरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, पैंथर्स पार्टी और बीजेपी से हैं। अगर वे काम करने के इच्छुक हैं और आप की नीतियों में विश्वास करते हैं, तो उनका पार्टी में स्वागत है।'

खान ने कहा कि कई राजनेता, पूर्व नौकरशाह और सामाजिक कार्यकर्ता आप के संपर्क में हैं और आने वाले पांच से दस दिनों में घटनाक्रम सामने आएगा। कई नेता और प्रमुख हस्तियां हमारे संपर्क में हैं। फिलहाल उनका नाम लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन उनकी साख की जांच किए बिना और पार्टी आलाकमान की सहमति के बिना, हम उन्हें इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं देंगे। इसके अलावा, हम पूर्व शर्तों के साथ किसी भी प्रवेशकर्ता को स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा और याद किया कि कैसे आप ने पंजाब में उम्मीदवारों और सीएम चेहरे (भगवंत मान) की घोषणा करने के लिए लोगों की पसंद पर भरोसा किया।

कांग्रेस सांसदों का धरना

नई दिल्ली, 31 मार्च (एजेन्सी)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य सांसदों ने पार्टी के महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ गुरूवार को संसद के निकट धरना दिया।

इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करना चाहिए और किसी भी तरह की वृद्धि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महंगाई की सबसे ज्यादा मार गरीबों एवं मध्य वर्ग के लोगों पर पड़ रही है।

पार्टी सांसदों ने संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आरंभ होने से करीब डेढ़ घंटे पहले विजय चौक पर कांग्रेस के 'महंगाई मुक्त भारत' अभियान के तहत धरना दिया।

इसमें राहुल गांधी के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल और कई अन्य सांसद शामिल हुए। कांग्रेस सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की।

इस धरने के बाद राहुल गांधी ने संवाददाताओं से कहा, महंगाई, खासकर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में विरोध जता रही है। पिछले 10 दिनों में नौ बार बढ़ोतरी की गई है। सरकार इस वृद्धि से हजारों करोड़ रुपये कमा रही है। इसकी सबसे ज्यादा चोट गरीबों और मध्य वर्ग पर पड़ती है।

उन्होंने यह भी कहा, हमारी मांग है कि सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम नियंत्रित करे और कीमतें बढ़ाना बंद करे।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, रसोई गैस सिलिंडर की कीमत दोगुनी हो गई है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 102 रुपये प्रति लीटर हो गई है। सरकार सिर्फ एक चीज कर रही है- गरीबों की जेब से पैसे निकालो और दो-तीन बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाओ।

कांग्रेस ने तीन चरणों में विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। गुरुवार को कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता लोगों के साथ-साथ अपने घरों और सार्वजनिक स्थानों के बाहर गैस सिलेंडर, स्कूटर/बाइक, खाली पेट्रोल/डीजल के डिब्बे आदि पर माल्यार्पण कर विरोध प्रदर्शन करेंगे और इन गतिविधियों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी करेंगे।

पार्टी द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि मोदी सरकार द्वारा भारत के लोगों को धोखा दिया गया है। 2 से 4 अप्रैल के बीच सुबह 11 बजे जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित जिला मुख्यालय पर लोगों की भागीदारी के साथ 'महंगाई मुक्त भारत धरना और मार्च' होगा।

'7 अप्रैल को, पार्टी कार्यकर्ता, फ्रंटल संगठन, विभाग और प्रकोष्ठ, श्रमिक संघों, यूनियनों और नागरिक समाज समूहों के साथ, प्रदेश कांग्रेस समितियों द्वारा आयोजित राज्य मुख्यालय में एक समान 'महंगाई मुक्त भारत धरना और मार्च' आयोजित करेंगे।'

सरकारी तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने पिछले दस दिनों में नौवीं बार गुरुवार को फिर से ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की है।

पेट्रोल-डीजल की कीमतें नियंत्रित करे सरकार : राहुल गांधी

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 01:00 PM
DEAR PADMA MORNING
Draw No:70 DrawDate on:31/03/22
1st Prize ₹1 Crore/- 41L 21715
Cons. Prize Rs.1000/- 21715 (REMAINING ALL SERIALS)
2nd Prize ₹9000/-
03781 04341 06611 07058 30655 31540 38399 50040 56436 68946
3rd Prize ₹450/-
0209 0420 0533 2905 3275 4882 5508 5800 7905 9310
4th Prize ₹250/-
2354 2527 3601 3685 3766 4133 6207 6334 6856 7432
5th Prize ₹120/-
0034 0141 0174 0187 0234 0274 0305 0348 0394 0427
0457 0540 0692 0997 1030 1176 1425 1506 1610 1693
1855 1922 1979 1981 2008 2184 2195 2329 2335 2346
2361 2373 2467 2793 2950 3016 3182 3333 3447 3606
3692 3820 4057 4113 4166 4183 4185 4276 4443 4543
4648 4759 4936 5068 5153 5337 5378 5436 5525 5719
5773 5806 5896 5900 5950 5969 6058 6178 6190 6208
6285 6297 6573 6641 7055 7157 7404 7463 7519 7565
7730 7845 7893 7940 7987 8074 8114 8184 8698 9028
9091 9101 9126 9156 9257 9317 9806 9886 9900 9905
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 08:00 PM
DEAR FALCON EVENING
Draw No:170 DrawDate on:31/03/22
1st Prize ₹1 Crore/- 76G 05280
Cons. Prize Rs.1000/- 05280 (REMAINING ALL SERIALS)
2nd Prize ₹9000/-
12537 14808 55680 66201 72734 77749 88938 89367 96875 97854
3rd Prize ₹450/-
0109 2016 2991 3201 3535 5575 7212 7269 9476 9750
4th Prize ₹250/-
0383 2219 6197 6423 7204 7705 7891 9555 9606 9754
5th Prize ₹120/-
0069 0082 0130 0136 0152 0160 0528 0782 0809 0868
0924 0974 1332 1420 1451 1470 1557 1652 2124 2128
2217 2271 2327 2343 2355 2426 2541 2709 2912 2913
2954 3273 3414 3629 3675 3735 3783 3837 3894 4002
4121 4146 4212 4426 4609 4638 5019 5124 5173 5219
5230 5353 5390 5500 5518 5561 5601 5648 5963 6015
6082 6367 6430 6487 6558 6642 6701 6896 7106 7181
7265 7340 7341 7347 7348 7366 7374 7527 7607 7632
7695 7738 7805 8103 8147 8192 8255 8410 8422 8642
8671 8933 9061 9296 9320 9408 9745 9805 9829 9906
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 06:00 PM
DEAR VENUS THURSDAY
Draw No:70 DrawDate on:31/03/22
1st Prize ₹1 Crore/- 83C 25635
Cons. Prize Rs.1000/- 25635 (REMAINING ALL SERIALS)
2nd Prize ₹9000/-
00521 18884 29547 38526 39191 44975 45021 45661 60904 72304
3rd Prize ₹450/-
0523 1853 3836 3934 5466 6259 6659 8471 8879 9835
4th Prize ₹250/-
0443 0629 0825 3536 3939 3941 4306 6967 7116 8915
5th Prize ₹120/-
0026 0054 0180 0222 0249 0285 0289 0338 0432 0502
0553 0756 0781 1064 1373 1496 1588 1732 1743 1811
1822 2052 2224 2812 3027 3211 3229 3487 3639 3646
3794 3808 3846 4069 4147 4208 4506 4570 4580 4586
4771 4811 4866 4908 4942 4957 4964 4982 5032 5036
5069 5237 5299 5301 5359 5369 5472 5495 5547 5583
5678 5970 5981 5983 6152 6180 6209 6254 6318 6863
6892 6951 6966 6975 6990 7005 7015 7132 7195 7231
7297 7385 7401 7484 7795 7834 7987 8048 8103 8187
8245 8270 8290 8680 9077 9155 9234 9353 9551 9767
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

संपादकीय पृष्ठ

समझौते ने दिखाई राह

असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों के बीच मंगलवार को हुआ सीमा समझौता 50 साल पुराने विवाद को सुलझाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस समझौते के जरिए दोनों राज्यों ने 12 विवादित स्थलों में से छह को लेकर सहमति हासिल कर ली। अब इस तय फॉर्म्युले के मुताबिक सर्वे किए जाने के बाद सीमाओं का पुनर्निर्धारण होगा और फिर उस पर संसद की मंजूरी ली जाएगी। इन औपचारिकताओं में कुछ और महीने लगेंगे, लेकिन विवादों की वजह से दोनों राज्यों के बीच जिस तरह का तनावपूर्ण माहौल लंबे समय से बना हुआ था, इस समझौते ने उसे खत्म कर दिया है। हालांकि विवाद के बिंदु अभी बरकरार हैं।

जानकारों के मुताबिक जो बचे हुए छह विवादित स्थल हैं, उन्हें सुलझाना थोड़ा मुश्किल है। जाहिर है, आगे की राह और चुनौतीपूर्ण साबित होने वाली है। लेकिन फिर भी इस समझौते ने अंतहीन से लगते विवादों को सुलझाने की राह दिखाई है। ध्यान रहे, नॉर्थ ईस्ट के चार राज्य- नगालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम- पहले असम का ही हिस्सा थे। अलग होने के समय से ही सीमावर्ती कुछ इलाकों को लेकर इनमें मतभेद रहे, जो कभी सही ढंग से सुलझाए नहीं जा सके। हालांकि सुलझाने के प्रयास जरूर किए गए समय-समय पर।

असम-मेघालय विवाद को ही लें तो 1985 में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया और कैख्नटन डबल्यू ए संगमा की पहल पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाय वी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। ऐसे और भी प्रयास हुए, लेकिन ये तमाम प्रयास नतीजा देने में नाकाम रहे। पिछले साल जुलाई से शुरू किए गए ताजा प्रयास अगर कामयाब हो रहे हैं तो उसके पीछे कई फैक्टर हैं। इसके लिए बनाई गई क्षेत्रीय कमिटी ने संबंधित इलाकों का गहन दौरा कर स्थानीय निवासियों से बातचीत के जरिए समस्या की जटिलता को समझा और उन्हें विश्वास में लिया।

दूसरे, एक ही बार में पूरी समस्या को हल करने के बजाय इसे टुकड़ों में बांटकर धीरे-धीरे सहमति बनाते और उसे समझौते का रूप देते हुए आगे बढ़ने की राह अपनाई गई। तीसरी बात यह कि दोनों राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व का संपूर्ण समर्थन इन प्रयासों को हर कदम पर उपलब्ध रहा। केंद्र सरकार की ओर से दी गई प्रेरणा भी इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उत्प्रेरक का काम करती रही।

बहरहाल, इस महत्वपूर्ण सफलता के लिए केंद्र और राज्य सरकारें निस्संदेह बधाई की हकदार हैं। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि ऐसे समझौतों की असल परीक्षा बाद के वर्षों में इन पर अमल के दौरान होती है। सीमा के दोनों तरफ दोनों राज्यों में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि स्थानीय आबादी में इस समझौते को लेकर किसी तरह की गलफहमी जड़ न जमाए और इसके प्रति स्वीकार्यता का भाव बना रहे।

जोखिम घटाने और भरोसा लौटाने का वक्त

वरुण गांधी

भारत में खुदरा निवेशकों ने पिछले तीन हफ्तों में 15 लाख करोड़ रुपये एक झटके में गंवा दिए। इस नुकसान की वजह कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि, सुस्त अर्थव्यवस्था और यूक्रेन संकट है। इनमें कई निवेशकों ने पहली बार बाजार में उत्साह के साथ निवेश किया था, पर उन्हें निराशा हाथ लगी। हमारे देश के कई युवा निवेशक अपनी बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी में लगाते हैं, जबकि अन्य आकर्षक बचत योजनाओं का रुख करते हैं, जिसमें धोखाधड़ी की आशंका रहती है। इस दौरान सूचीबद्ध शीर्ष कॉरपोरेट ने भी अपनी चमक गंवाई है।

नई कंपनियां आईपीओ के जरिये खुदरा निवेशकों को मोटी कमाई का प्रस्ताव देती हैं, पर ऐसी कंपनियां अब सार्वजनिक निर्गम के अधिक मूल्य निर्धारण के लिए कुख्यात हैं। इसमें पेटीएम का मामला तो खासा चर्चित रहा। इसके शेयर की कीमत लगातार गिर रही है, जो आईपीओ मूल्य से काफी कम है। इस बीच, बाजार को लेकर दिखे उत्साह ने कॉरपोरेट गवर्नेंस की चुनौतियों को छिपाया है। एनएसई में देखी गई अनियमितताओं ने एक गहरी संस्थागत सड़ांध को उजागर किया है।

इस बीच सेबी अपने पहले के रुख से पलट गई है, जिसमें शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों को अध्यक्ष और एमडी की भूमिका को अलग करने की बात कही गई थी। यह नियामकीय कब्जे का नया संकेत है। देश की शीर्ष 500 कंपनियों में से 300 प्रमोटर-संचालित हैं। ऐसे में ये कंपनियां दोनों भूमिकाएं साथ निभाना जारी रखती हैं, जिससे बोर्ड की जिम्मेदारियों और रोजमर्रा के दायित्वों के बीच हितों का टकराव स्वाभाविक होता है। ताजा एबीजे शिपयार्ड घोटाले में 28 बैंकों के 22,842 करोड़ रुपये का डूबना दिखाता है कि एनपीए का संकट गहराता जा रहा है।

सूचीबद्ध कंपनियों से इस्तीफा देने वाले स्वतंत्र निदेशकों की बढ़ी संख्या दिखाती है कि कई कंपनियां धोखाधड़ी में लिप्त हैं। हमारे पास निवेशक संरक्षण के लिए विनियमन के दायरे और वास्तविक फंडिंग सीमित हैं। एनएसई के पास 594 करोड़ रुपये का निवेशक सुरक्षा कोष था, जबकि बीएसई के पास मार्च, 2020 तक यह कोष 784 करोड़ रुपये का था। जाहिर है, निवेशक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के साथ सेबी को अपने कॉरपोरेट प्रशासन मानदंडों की समीक्षा करने की सख्त जरूरत है। इस दौरान नई निवेश योजनाओं में भी कई निवेशकों के पैसे डूबे हैं।

एक आंकड़े के मुताबिक, पांच लाख भारतीयों ने मल्टीलेवल मार्केटिंग योजनाओं में मई और जून, 2021 के महज दो महीने में 150 करोड़ रुपये गंवा दिए। ये धोखाधड़ी पावरबैंक और ऐजख्नलान जैसे ऐप के जरिये हुई। निवेशकों के साथ झांसे का यह खेल अपने तंत्र और विस्तार में कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इससे लग सकता है कि बीते दिसंबर में गूगल ख्नलेस्टोर से ऐसे 400 अनधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले ऐप हटाए गए थे। इसी महीने यह भी पता चला कि लाखों निवेशकों ने चिटफंड धोखाधड़ी मामले में (एग्री गोल्ड फार्म एस्टेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ) 6,800 करोड़ रुपये गंवा दिए।

इस बीच क्रिख्नटो-मुद्रा, जो अपने-आप में एक विशाल अनियमित क्षेत्र है, ने नई चुनौती पेश की है। बिटकनेक्ट के संस्थापक सतीश कुंभाणी 2.4 अरब डॉलर की वैश्विक पोंजी योजना व्यवस्थित करने और न्यूयॉर्क में आरोपी ठहराए जाने के बाद भारत से भाग गए। अगस्त, 2017 में नोएडा में 15,000 करोड़ रुपये का बाइक बॉट घोटाला हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश के निवासी संजय भाटी ने एक साधारण योजना के माध्यम से दो लाख से अधिक निवेशकों को 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का धोखा दिया।

इसके तहत एक साधारण बाइक के लिए 62,100 रुपये के निवेश के लिए लोगों को उकसाया गया था और बदले में उन्हें सालाना 1.17 लाख रुपये का मुनाफा देने का वादा किया गया था। कहने को तो देश में निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए नियामकीय ढांचा है, पर यह निष्प्रभावी है। मौजूदा सूरतेहाल में निवेशक जागरूकता में सुधार करने और चिटफंड योजनाओं की समीक्षा करने के लिए एक संस्थागत प्रणाली विकसित करने की जरूरत है। ऐसी प्रणाली आदर्श रूप से योजना को पहले से सत्यापित करेगी और भुगतान एकत्र करने के लिए मध्यस्थ मंच के रूप में काम करेगी।

हमें आम भारतीयों को यह समझाने के लिए भी एक तंत्र की आवश्यकता है कि कोई योजना उनके लिए युक्तिसंगत है या नहीं। आधार, यूपीआई और जीएसटी के बीच एकीकरण ऐसी प्रणाली को पुख्ता करने में मदद कर सकता है। जो निवेशक बैंक खातों में पैसा जमा रखते हैं, उनके लिए भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। धोखाधड़ी के मामलों में वहां भी वृद्धि हुई है। आरबीआई का आंकड़ा बताता है कि देश में अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021 के बीच 36,342 करोड़ रुपये की 4,071 बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। इनमें इंटरनेट और कार्ड से जुड़े लेनदेन के मामले 34.6 फीसदी थे।

इसके समाधान के लिए पीएसयू बैंकों को महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने और सख्त केवाईसी मानदंडों को अनिवार्य करने की जरूरत है। हमें व्यावसायिक हितों वाले लोगों पर बैंकों (सहकारिता सहित) के बोर्ड में शामिल होने पर सख्त प्रतिबंध लगाना चाहिए। ऐसे लोग, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के लिए सरकार पर भरोसा रखा है, वे भी असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) खातों से अवैध धन निकासी के मामले पिछले एक साल से खासे बढ़े हैं। इस बाबत आई रिपोर्ट दिखाती है कि कैसे ईपीएफओ कर्मचारियों ने फर्जी दस्तावेज और मोबाइल नंबरों के जरिये बंद कंपनियों से कथित तौर पर पैसे निकाले हैं।

खुद सीबीआई ने ऐसे मामलों में 18.97 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप में ईपीएफओ के 18 अधिकारियों को पकड़ा है। जाहिर है, ईपीएफओ के कामकाज में ज्यादा पारदर्शिता और कर्मचारियों के हित और सुरक्षा के लिए इसे नए सिरे से सुदृढ़ करने की जरूरत है। गबन और धोखे के ऐसे तमाम मामलों को देखते हुए खुदरा निवेशकों की हिफाजत के लिए ठोस पहल जरूरी है।

निवेशकों की जागरूकता और उनकी सुरक्षा के लिए संस्थागत उपायों का दायरा और तंत्र फिलहाल खासा कमजोर है। साथ ही खुदरा निवेशकों के निवेश के लिए कम जोखिम वाले विकल्पों को और बढ़ाना होगा। हमें बुनियादी तौर पर आधुनिक बैंकिंग ढांचे की जरूरत है, जो ऐसे धोखों को रोकने में कारगर हो।

सामाजिक न्याय की दरकार

डॉ. फैयाज अहमद फैज

एक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश की नवनियुक्त भाजपा सरकार ने अपनी परंपरा से हटते हुए मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के प्रश्न को दृष्टिगोचर रखते हुए देशज पसमांदा समाज से आने वाले अपने कैडर दानिश आजाद को मंत्रालय में जगह दी है।

ज्ञात रहे कि अब तक भाजपा में शिया सैय्यद ही ऐसे उच्च पदों पर आसीन होते रहे हैं। भारत के राजनैतिक इतिहास में यह दूसरी घटना है जहां एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी ने मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए जातीय संरचना में पिछड़े कहे जाने वाले समाज को भागीदारी दी है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम विमर्श की वकालत करती मुस्लिम लीग के विरोध में उस समय के आसिम बिहारी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के लिए संघर्षरत जमीयतुल मोमिनीन (मोमिन कॉन्फ्रेंस) ने संगठन और पसमांदा समाज की साधनविहीनता (उस समय वयस्क मतदान का अधिकार नहीं था और पढ़े-लिखे एवं पैसे वाले लोगों को ही मतदान का हक था जिससे पिछड़ा समाज लगभग वंचित था) के बावजूद मुस्लिम लीग को 1946 के चुनाव में अनेक सीटों पर मात दी थी जिसका संज्ञान लेते हुए सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के बाद बिहार में बनने वाली सरकार में कांग्रेस की अशराफ लीडरशिप के विरोध के बावजूद मोमिन कॉन्फ्रेंस के दो साथियों नूर मुहम्मद और अब्दुल कय्यूम अंसारी को कांग्रेस की शपथ पर हस्ताक्षर कराए बिना मंत्रिमंडल में शामिल करवाया था।

ऐसा नहीं है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद ही इस ओर ध्यान दिया है। चुनाव से बहुत पहले ही उसने अल्पसंख्यक आयोग, मदरसा बोर्ड और उर्दू अकादमी के अध्यक्ष पदों पर पसमांदा समाज से आने वालों की नियुक्ति कर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी। यह बात ध्यान देने की है कि अब तक इन अल्पसंख्यक संस्थानों के अध्यक्ष पद पर पारंपरिक रूप से लगभग सभी पार्टियों द्वारा मुस्लिम समाज के उच्च शासकवर्गीय अशराफ मुसलमानों को ही नियुक्त किया जाता रहा है। हुनर हाट के आयोजन के माध्यम से भी मुस्लिम समाज की वंचित पिछड़ी जातियों को जोड़ने का प्रयास किया गया। मुस्लिम पिछड़ी जातियों में अधिकतर कामगर जातियां आती हैं, जो हुनर हाट जैसे कार्यक्रम से सीधे संबंधित हैं। आगामी लोक सभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यूपी मंत्रीमंडल में पसमांदा को शामिल कर इस दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। ज्ञात रहे कि पसमांदा मुसलमान कुल मुस्लिम संख्या का 90ञ हैं। इनमें से कुछ प्रतिशत को भी पार्टी प्रभावित कर ले गई तो मुस्लिमों की बड़ी संख्या का वोट उसके पक्ष में हो सकता है।

पसमांदा आंदोलन के साथी चुनाव के दौरान लगातार मांग कर रहे थे कि पूर्वांचल की बुनकर बेल्ट से बुनकर को टिकट दिया जाए लेकिन प्रमुख विपक्षी पार्टी ने बुनकरों का वोट तो भरपूर लिया किंतु टिकट देना गवारा नहीं किया। दानिश आजाद पूर्वांचल के बुनकर समाज से आते हैं, जहां बुनकरों की बड़ी संख्या आबाद है। दानिश आजाद के मंत्रीमंडल में शामिल होने के साथ ही मुस्लिम समाज के सामाजिक न्याय का प्रश्न एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सोशल मीडिया में खुलेआम अशराफ वर्ग के नौजवानों और बुजुगरे, जिनमें खुद को सेक्युलर, लिबरल, कट्टर धार्मिक और राष्ट्रवादी कहने वाले लगभग सभी प्रकार के लोग हैं, द्वारा जातिसूचक अपमानजनक शब्द जुलाहा का प्रयोग कर पूरे पसमांदा समाज के मान-सम्मान को तार-तार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसे आप चंद लोगों के मानसिक दिवालियापन का नाम दे सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शहजाद अब्बास द्वारा एक चैनल डिबेट में यह कहना कि शिया को भागीदारी न देकर पसमांदा के नाम पर ऐसे चेहरे को मंत्री बनाना जिसे कोई नहीं जानता, मुसलमानों का अपमान है। इससे अर्थ निकलता है कि सैय्यद मंत्री बने तो मुसलमानों का सम्मान और देशज पसमांदा बने तो मुसलमानों का अपमान है। एक यूट्यूब चैनल पर वरिष्ठ पत्रकार सैय्यद कासिम ने बुनकर समाज को मुसलमानों में आर्थिक और शैक्षिक रूप से सबसे मजबूत बिरादरी बताया। उन्हें कमजोर तबका मानने से इंकार किया जबकि यह पूर्णत: सत्य से परे है। मंडल कमीशन, रंगनाथ मिश्र कमीशन और सच्चर कमेटी की रिपोटरे के आधार पर मुस्लिम बुनकर समाज हर रूप से पिछड़ा है, और इसी कारण केंद्र और राज्य की आरक्षण लिस्ट में अन्य पिछड़े वर्ग में आता है जबकि हिंदू समाज का बुनकर वर्ग अनुसूचित जाति में आता है।

उर्दू मीडिया भी दानिश आजाद से आरएसएस की विचाराधारा से संबंधित असहज सवाल पूछ रहा है। शायद ही कभी उर्दू मीडिया ने भाजपा के किसी अशराफ लीडर से ऐसे सवाल किए हों। क्या आपने कभी देखा है कि किसी हिंदू पिछड़े दलित को राजनैतिक भागीदारी मिलने पर सवर्ण समाज की तरफ से सोशल मीडिया पर इस प्रकार से गाली-गलौज की जाती हो या किसी राजनैतिक पार्टी के प्रवक्ता द्वारा एक वंचित को राजनैतिक भागीदारी मिलने पर हिंदू समाज का अपमान बताया जाता हो? जबकि यही लोग इससे पहले शिया-सैय्यद लोगों के मंत्री बनाए जाने पर लगभग खामोश रहा करते थे।

कुशीनगर के रामकोला में भाजपा कार्यकर्ता बाबर की हत्या के पीछे यही मानसिकता उत्प्रेरक की भूमिका में प्रतीत होती है। इसका एक ऐतिहासिक पक्ष भी है, 1946 के इलेक्शन में कानपुर में एक पसमांदा कार्यकर्ता अब्दुल्लाह की मुस्लिम लीग के खिलाफ प्रचार करने के कारण हत्या करवा दी गई थी। होना तो यह चाहिए था कि मुस्लिम समाज का नेतृत्व करने वाले अशराफ वर्ग को अपने द्वारा संचालित संस्थाएं जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारते शरिया आदि में मुस्लिम समाज के वंचित तबकों को भी भागीदारी देकर सामाजिक न्याय की स्थापना करनी चाहिए न कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार में पसमांदा की भागीदारी पर इस तरह का क्षोभ प्रकट करे।

इस पूरे प्रकरण से यह बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि मुस्लिम समाज में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं, और समाज में सामाजिक न्याय की तत्काल कितनी गंभीर रूप से आवश्यकता है।

राजस्थान में सीरियल ब्लास्ट की साजिश नाकाम, 3 गिरफ्तार

जयपुर, 31 मार्च (एजेन्सी)। राजस्थान पुलिस ने चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा शहर से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले 12 किलोग्राम विस्फोटक और अन्य सामग्री जब्त की है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

शुरुआती जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति- जुबैर, अल्तमास और सैफुल, अल सूफा संगठन से जुड़े हैं जो मध्य प्रदेश में रतलाम और देवास के पास से ऑपरेटस होता है।

उन्हें उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वे मध्य प्रदेश की नंबर ख्नलेट वाली बोलेरो कार में जा रहे थे। कहा जा रहा है कि वे रतलाम (मध्य प्रदेश) से विस्फोटक सामग्री लेकर जयपुर जा रहे थे।

इस संबंध में निम्बाहेड़ा के सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

आरोपियों से पूछताछ के बाद इस मामले में टोंक और चित्तौड़गढ़ से तीन और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है।

पूछताछ के दौरान पता चला कि जयपुर में एक सीरियल ब्लास्ट की साजिश रची गई थी और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को विस्फोटक अपने समूह के अन्य सदस्यों को सौंपना था।

इस जांच के आधार पर राजस्थान और मध्य प्रदेश से पांच अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है।

अधिकारियों को संदेह है कि संभवत: तीन स्थानों पर सिलसिलेवार विस्फोट करने की योजना थी।

इस बीच, मध्य प्रदेश के रतलाम में एटीएस टीम ने कथित तौर पर 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के किसी आतंकी संगठन से जुड़े होने की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो भी इस मामले पर नजर रख रही है।

अधिकारियों ने कहा कि गिरफ्तार किए गए तीन लोगों से पूछताछ की जा रही है और उनके स्लीपर सेल का हिस्सा होने की संभावना है।

बेहतर सुविधाओं से सुधरते हालात

भगवती प्रसाद डोभाल

भारत में किसी जमाने में गर्भधारण करने से लेकर बच्चा पैदा होने तक खराब खान-पान और लापरवाही की वजह से माताओं की मृत्यु-दर का अनुपात बहुत ज्यादा होता था।

लेकिन अब भारत ने इस विकराल समस्या पर अंकुश लगाने में सफलता पा ली है। इस कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन को रिपोर्ट जारी करनी पड़ी है कि भारत में माताओं के स्वास्थ्य की उम्दा देखभाल के कारण मृत्यु-दर का ग्राफ काफी नीचे चला गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक मानक तैयार किया हुआ है, जिसके अंर्तगत वे महिलाएं आती हैं, जो गर्भवती हो जाती हैं, और बच्चा पैदा करने के बाद 42 दिनों तक स्वस्थ रहती हैं। यदि उनकी इस बीच मृत्यु हो जाती है, तो इसे मातृ-मृत्यु में शामिल किया जाता है।

इसी मानक को आधार मानकर रजिस्ट्रार जनरल के सेंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी एसआरएस कार्यालय ने भारत की 2017-19 में मातृ मृत्यु-दर यानी एमएमआर पर विशेष बुलेटिन जारी किया है। इस सव्रे के अनुसार एक लाख बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृ-मृत्यु दर यानी एमएमआर कहते हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया गृह मंत्रालय के अधीन है। जनसंख्या की गणना करने और देश में जन्म-मृत्यु का पंजीकरण रजिस्ट्रार जनरल के अंदर ही होता है। पंजीकरण के अलावा नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी एसआरएस का उपयोग करके प्रजनन और मृत्यु-दर के संबंध में अनुमान भी लगाया जाता है। एसआरएस देश का सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय नमूना सव्रेक्षण है, जिसके अन्य संकेतक राष्ट्रीय प्रतिनिधि नमूने के माध्यम से मातृ मृत्यु-दर जानने के करीब पहुंचते हैं। वर्बल ऑटोख्नसी या वीए उपकरणों को नियमित आधार पर एसआरएस के माध्यम से दर्ज मौतों के लिए प्रबंधित किया जाता है, ताकि देश में एक विशिष्ट कारण से होने वाली मृत्यु-दर का पता लगाया जा सके। एमएमआर को लेकर भारत में मातृ मृत्य-दर में 10 अंकों की गिरावट आई है। यह 2016-18 के 113 से घट कर वर्ष 2017-18 में 103 हो गई थी, जो 8.8 फीसदी की गिरावट थी। देश में मातृ मृत्यु-दर वर्ष 2014-16 में 130, वर्ष 2015-17 में 122, 2016-18 में 113 और वर्ष 2017-19 में 103 रह गई थी। भारत ने 2020 में एक लाख बच्चों के जन्म पर 100 माताओं की मृत्यु पर लाने का लक्ष्य रखा था। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति यानी एनएचपी के लक्ष्य को प्राप्त करने के काफी करीब है, और 2030 तक एक लाख शिशुओं के जन्म पर 70 माताओं को खोने की स्थिति हो सकती है।

बहुत सारे विकसित देशों ने मातृ मृत्यु-दर को एकल अंक तक पहुंचा दिया है। इनमें इटली, पोलैंड और बेलारूस में एक लाख शिशुओं के जन्म पर सिर्फ दो माताओं की मौतें होती हैं, जबकि जर्मनी और ब्रिटेन में सात माताएं एक लाख शिशुओं के जन्म होने पर चल बसती हैं। कनाडा और अमेरिका में दस और उन्नीस माताएं दुनिया से विदा हो जाती हैं। भारत के अधिकांश पड़ोसी देशों-नेपाल में 186, बांग्लादेश में 173 और पाकिस्तान-में 140 मातृ मृत्यु दर है जबकि चीन और श्रीलंका ने मातृ स्वास्थ्य पर काफी ध्यान केंद्रित हुआ है। यहां 18 और 36 माताएं काल का ग्रास बनती हैं।

भारत में राज्यवार स्थिति देखें तो केरल 30, महाराष्ट्र 38, तेलंगाना 56, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश 58, झारखंड 61 और गुजरात में 70 माताओं ने जीवन त्यागा। केरल में सबसे कम मातृ मृत्यु-दर है। यहां 12 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। यह राष्ट्रीय मृत्यु-दर से कम है। 2015-17 में केरल ने मातृ मृत्यु-दर को 42 के स्तर पर रोक दिया था। अब नौ राज्यों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति द्वारा निर्धारित मातृ मृत्यु-दर को हासिल कर लिया है। उन राज्यों में कर्नाटक 83 और हरियाणा 96 भी अब शामिल हो गए हैं। उत्तराखंड 101, पश्चिम बंगाल 109, पंजाब 114, बिहार 130, ओडिशा 136 और राजस्थान में 141 मातृ मृत्यु-दर है। छत्तीसगढ़ 160, मध्य प्रदेश 163, उत्तर प्रदेश 167 और असम 205 पर हैं।

मातृ मृत्यु-दर को रोकने में सरकारी पहल भी हुई हैं, और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी प्रयास करता आ रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के भीतर जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनाएं भी देश में चल रही हैं। पर देखने में आया है कि शहरों की अपेक्षा ग्रामीण माताएं मृत्य का ज्यादा शिकार होती हैं। इसके पीछे कुप्रबंधन भी देखने को मिलता है। स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण इलाकों में समय पर उपलब्ध नहीं हो पातीं। इसमें दवा और एंबुलेंस का अभाव अक्सर खटकता है। इसके लिए सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह से निजी क्षेत्र में नहीं देना चाहिए। उतना ही देना चाहिए जितना नागरिक उनके खचरे को वहन कर सकते हों। सरकारी अस्पतालों की सेवाओं को हर स्तर पर बढ़ाया जाना चाहिए ताकि भारत का हर तबका स्वास्थ्य लाभ पाने के योग्य हो सके।

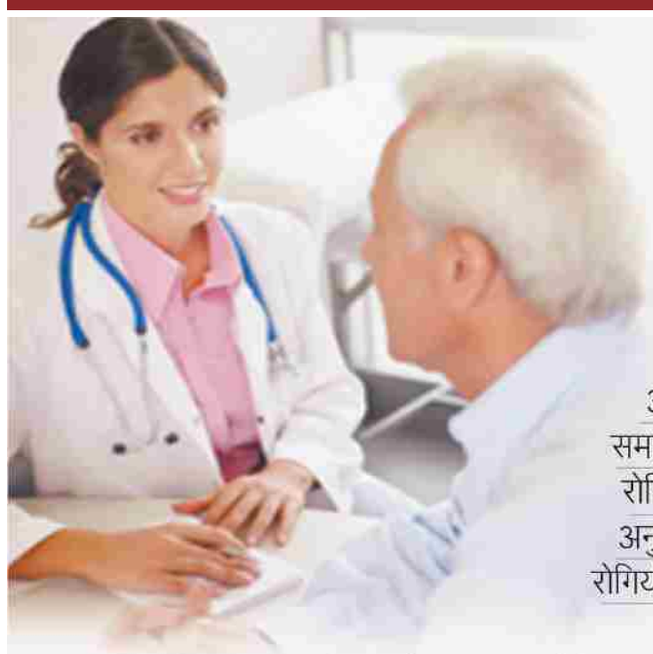

उम्रदराज लोगों को होता है ऑस्टियोपोरोसिस

अक्सर उम्रदराज लोगों को आपने जोड़ों के दर्द की शिकायत करते सुना होगा, हड्डियों में तकलीफ की समस्या भी आम होती है। वृद्धों की इस आम समस्या को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। इस बीमारी के रोगियों में रजोनिवृत्ति (मेनोपॉज) प्राप्त महिलाओं और उम्रदराज लोगों की संख्या ही ज्यादा होती है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में लगभग दस करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। केवल भारत में इसके रोगियों की संख्या लगभग छह करोड़ दस लाख है, जिसमें 60-70 प्रतिशत महिलाएं हैं। पुरुषों को इस रोग का खतरा चालीस वर्ष की उम्र से तो महिलाओं को लगभग पैंतीस वर्ष की उम्र से होता है।

इस बीमारी में हड्डियां भुरभरी हो जाती हैं। साथ ही हड्डियों के ऊतकों का घनत्व कम हो जाता है, इस कारण किसी भी झटके से उनके टूटने की आशंका बढ़ जाती है।

उम्र का बढ़ना और कैल्शियम की कमी ऑस्टियोपोरोसिस को आमंत्रित करने वाले मुख्य कारण हैं। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, इसकी कमी से हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं और उनके टूटने की दर बढ़ जाती है। रजोनिवृति के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन हारमोन की कमी के कारण इस रोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

नीचे झुकने या सामान्य अवस्था में कमर दर्द होना और झुकने से कद कम होना इस बीमारी के सामान्य लक्षण हैं। इस बीमारी से अक्सर रीढ़ की हड्डी में भी विकृति आ जाती है, अतः रीढ़ की हड्डी में थोड़े से भी परिवर्तन को हल्के तौर पर ना लें। रोजमर्रा के काम जैसे कुछ चीज उठाने के लिए नीचे झुकने, बिस्तर बिछाने के लिए नीचे झुकने या किसी हल्के झटके जैसे बस या आटो रिक्शा की पिछली सीट पर लगे झटके से हड्डियों में बार-बार होने वाला फ्रैक्चर भी ऑस्टियोपोरोसिस की निशानी है।

यों तो सम्पूर्ण शरीर की हड्डियां इससे प्रभावित होती हैं। परन्तु सामान्य रूप से कूल्हे, कलाई और रीढ़ की हड्डियां ही इस रोग की मुख्य शिकार होती हैं। इसके परिणाम इस कदर भयंकर हो सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी टूटने से कंधे झुक सकते हैं और कद छह इंच तक कम हो सकता है। कूल्हे का फ्रैक्चर होने की स्थित मिं अक्सर शल्य चिकित्सा के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। ऐसे रोगियों के अध्ययनों से यह निष्कर्ष सामने आया है कि कूल्हे के फ्रैक्चर वाले लगभग पचास प्रतिशत रोगी पूर्णतया ठीक नहीं हो पाते, वे सदा के लिए ही बिस्तर से बंध जाते हैं।

इस बीमारी का पता लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है विशेषकर महिलाओं में आसानी से इसका पता लग सकता है। वैसे तो बोन डेनसिटीमीटर से कुछ ही पलों में इस रोग का पता लगाया जा सकता है, पर एक साधारण से रिस्ट टेस्ट के द्वारा इस रोग का घर बैठे ही पता लगाया जा सकता है। इसके लिए कुछ साधारण प्रश्न आप खुद से पूछ सकती हैं, जिससे पता चला सकता है कि आपको यह बीमारी होने की आशंका है कि नहीं।

- क्या आप एक रजोनिवृत्त महिला हैं और क्या आपको पैंतालीस वर्ष की आयु से पहले ही रजोनिवृत्ति हो गई थी?
- क्या आप शारीरिक तौर पर सक्रिय नहीं हैं?
- क्या आप अपने आहार में कैल्शियमयुक्त खाद्य पदार्थ जैसे दूध और दूध से बनी चीजें कम लेती हैं?
- क्या आपकी या परिवार के किसी नजदीकी सदस्य की हड्डी किसी हल्के से झटके से टूटी है?
- क्या आप दमा या आर्थराइटिस के लिए कोर्टिकोस्टिरॉटड दवा छह महीने से ले रही हैं?

ऊपर लिखे प्रश्नों में से यदि एक प्रश्न का भी उत्तर हां है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस की आशंका हो सकती है, ऐसे में तुरंत डॉक्टरी सलाह लेना उचित रहेगा।

ऑस्टियोपोरोसिस का पता लगाने के लिए डॉक्टर अल्ट्रासाउंड बोन डेन्सिटोमीटर टेस्ट का सहारा लेते हैं। इससे अस्थियों में नुकसान की दर, फ्रैक्चर होने की संभावनाओं, इलाज के प्रभावों आदि की जानकारी मिल जाती है। इसमें एल्कोहल में भीगी रूई से टखनों के किनारों को साफ करके पैर को एक रेडिएशन फ्री मशीन के भीतर रखना होता है। मशीन में पैर फिट होने के बाद रीडिंग ली जाती है और दो मिनट में ही परीक्षण की रिपोर्ट सामने आ जाती है। जांच से पहले सामान्य खाना ही खाएं, इस बात का ध्यान रखें कि इस परीक्षण के चौबीस घंटे पहले कैल्शियम की खुराक न लें। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि परीक्षण से सात दिन पहले तक कोई बेरियम-स्टडी रेडियो आइसोटोप इंजेक्शन अथवा सीटी अथवा एम.आर.आई परीक्षण के लिए ओरल या आई.वी कान्ट्रास्ट न लिया गया हो।

कुछ आसान से छोटे-छोटे व्यायाम भी आपको इस बीमारी से बचा सकते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

- फर्श पर लेट जाएं। दोनों हाथों को पेट पर रखकर घुटनों को 90 डिग्री के कोण में मोड़ें। अब कंधों को जमीन से सटाकर रखें और सिर को ऊंचा उठाएं, फिर धीरे-धीरे नीचे ले जाएं। इसे दस-पन्द्रह बार दोहराना चाहिए।
- पेट के नीचे तकिया रखकर फर्श पर पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथ नितम्बों पर रखें। अब सिर को फर्श तक झुकाएं और फिर जितना उठा सकें उठाएं। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति दस से पन्द्रह बार करें।
- कुर्सी पर कुछ इस प्रकार बैठें कि आपकी पीठ कुर्सी से सटी हो। सिर के पीछे दोनों हाथों को क्रास करें। कोहनियों की पीछे की ओर खींचते हुए लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। ऐसा दस-पन्द्रह बार करें।
- हाथों और घुटनों के बल झुकें। एक घुटने को कमर की ऊंचाई तक ले जाएं फिर वापस पूर्व स्थिति में ले आंए। दूसरे पैर से यही व्यायाम करें। इस क्रिया को भी दस से पन्द्रह बार दोहराना उचित रहेगा।
- फर्श पर सीधे लेटें और दोनों हाथ पेट पर रखें। अब पैरों को फर्श से लगभग एक इंच ऊपर उठाएं इसमें ध्यान रखें कि घुटने आपस में जुड़े हों। इस स्थित मिं कुछ सेकेण्ड रुकने के बाद पैरों को नीचे ले आएं। ऐसे पांच से दस बार करें।
- कुर्सी पर पीठ लगाकर सीधे बैठें। बाहों को किनारे पर टिकाएं और पैरों को फर्श पर सीधे रखे। फिर अपने कंधों को पीछे की ओर धकेलने का प्रयास करे और फिर पहली वाली अवस्था में वापस आ जाएं। इसे भी दस या पन्द्रह बार दोहराएं।

एक अहम बात यह है कि इन व्यायामों को करने से पूर्व किसी विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लें।

जहां तक खान-पान का प्रश्न है, सदैव ऐसा संतुलित आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम हो, इसके साथ ही फल जैसे नाशपाती, केला, अमरूद और अंजीर आदि भी लें। दालें, बादाम, अखरोट, टमाटर, मूंगफली, सोयाबीन, राजमा, पत्तागोभी, मेथी, मछली और ऑयस्टर मांस की पर्याप्त मात्रा भी भोजन में शामिल की जानी चाहिए।

कैफीन और एल्कोहल से बचना फायदेमंद होता है। सिगरेट से बचना भी जरूरी है क्योंकि यह एक्ट्रोजन के स्तर को कम करती है और महिलाओं में रजोनिवृति के समय हड्डियों के घनत्व पर बुरा असर डालती है। कार्बोनेटिक पेय और सोड़ा आदि भी न लें क्योंकि इसमें उपस्थित फास्फोरस आपके शरीर में उपस्थित कैल्शियम की अतिरिक्त मात्रा में कमी कर सकता है।

ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम जरूरी है हर सांतवे से दसवें वर्ष में पुरानी हड्डियों का स्थान नई हड्डियां ले लेती हैं। बड़े होने पर मजबूत हड्डियां हों इसलिए बचपन से भी हड्डियों की मजबूती का ध्यान रखना जरूरी होता है।

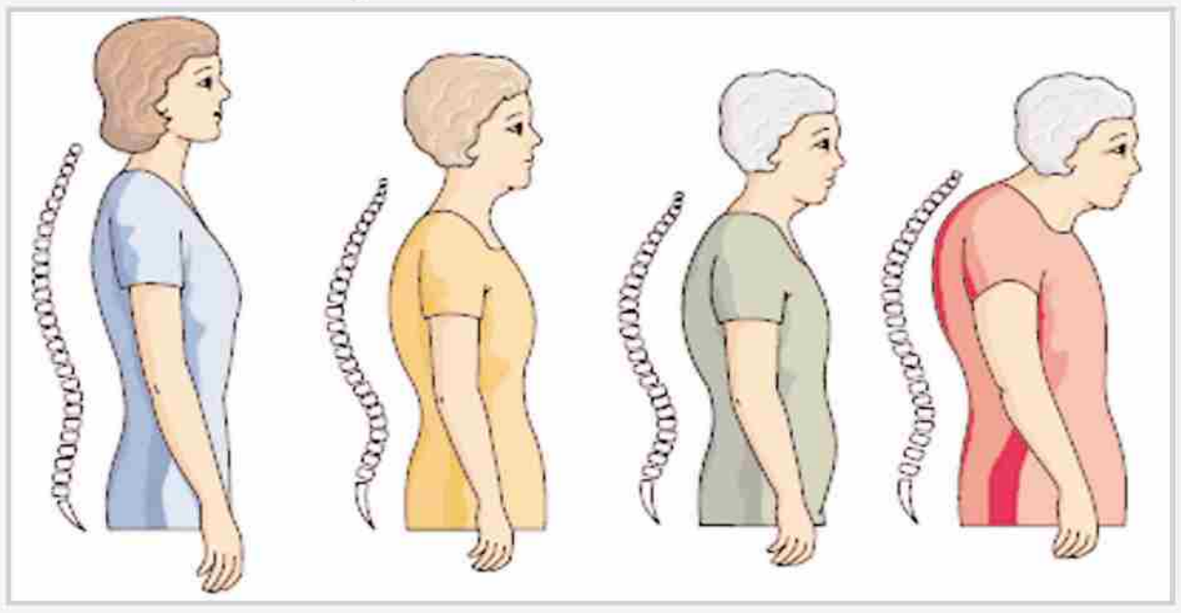

एक अनानास
करे कई बीमारियों का नाश

अनानास का नाम सुनते ही बच्चे हों या बड़े इसे खाने से कतराते हैं। देखने में खूबसूरत लगने वाला यह फल खाने में उतना ही खट्टा और एसिडिक होता है। मगर अनानास जूस से भरा बेहतरीन फल है। इसका ट्रापिकल फ्लेवर मीठे और खट्टे दोनों को सही बैलेंस करता है। गर्मी हो या सर्दी यह कभी भी खाया जा सकता है। मगर ज्यादातर लोग इसे गर्मी में खाना पसंद करते हैं। इसे नमक और चाट मसाले के साथ खाएं, तो यह स्वादिष्ट लगता है।

अनानास में विटामिन्स और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है। जैसे विटामिन ए और सी। कैल्शियम, पोटाशियम और फास्फोरस भी इसमे मौजूद होता हैं। फाइबर से युक्त और फैट व कोलेस्ट्राल बहुत कम होने के कारण सेहत के लिए इसे फायदेमंद माना जाता है। गर्मियों के लिए एक बेहतरीन फल है।

कफ और कोल्ड के वायरस से लड़ने के लिए इसमें विटामिन सी की सही मात्रा होती है। इसमें ब्रोमेलेन नामक पदार्थ होता है जो खांसी रोकने में मददगार है।

इसमें पाया जाने वाला मैग्नीज हड्डियों और उत्तकों को मजबूत बनाएं रखने में मददगार होता है। अनानास के लगातार सेवन से आपके मसूढ़े स्वस्थ और मजबूत रहते हैं।

अनानास मैकुलर डिजेनेरेशन से भी बचाता है। मैकुलर डिजेनेरेशन के कारण ही विजन लॉस होता है और रेटिना डैमेज होता है। इससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। मगर अनानास में मौजूद बीटा कैरोटीन इस खतरे को तीस प्रतिशत तक कम करने में मददगार होता है।

पाचन संबंधी समस्याओं के लिए अनानास का सेवन सबसे फायदेमंद है। यह पाचन क्रिया को दुरूस्त बनाने में मदद करता है। अनानास में मौजूद ब्रोमेलेन इसके रस को न्यूट्रल करता है जिस कारण यह ज्यादा एसिडिक नहीं हो पाता।

यह पैनक्रियाज से बनाने वाले रस को भी नियंत्रित करता हैं जो पाचन क्रिया में आगे मददगार होते हैं। पैनक्रियाज में नियंत्रण के कारण हम डायबिटीज जैसी बीमारी से भी सुरक्षित रह सकते हैं।

प्रेग्नेंसी में च्यूइंग गम!
खतरनाक

प्रेग्नेंसी के दौरान च्यूइंग गम ज्यादा खाने से बच्चा सील सिंड्रोम का शिकार हो सकता है। इस बीमारी में उसकी बॉडी तो नॉर्मल होगी लेकिन उसके हाथ-पैर छोटे बच्चे की तरह ही छोटे रहते हैं। कई बार पेशंट के पैरों में इतनी भी जान नहीं होती कि वह अपने पैरों पर खड़ा रह सके। इस बीमारी को भुगत रहे इराक के 46 साल के हुसैन अली राधी को जब हार्ट की बीमारी हुई तो उनके देश के डॉक्टर उनका इलाज करने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन दिल्ली के डॉक्टरों ने विश्व में पहली बार ऐसे पेशंट की एंजियोप्लास्टी करके तीन स्टेंट लगाने में कामयाबी हासिल की। इलाज के बाद हुसैन अब अपने देश जाने की तैयारी में हैं।

हाथ-पैर छोटे

मैक्स के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेका कुमार ने बताया कि हुसैन एक जनेटिक बीमारी के शिकार हैं, जिस वजह से उनके हाथ और पैर छोटे बच्चे की ही तरह हैं यानी हाथ और पैरों की ग्रोथ नहीं हो पाई है, जबकि बाकी पार्ट्स सामान्य इंसान की तरह हैं। इस बीमारी को सील सिड्रोम कहा जाता है। अमूमन हर 25 हजार बच्चों में से एक को यह बीमारी होती है। आमतौर पर इस बीमारी में बच्चे का कद छोटा हो जाता है, लेकिन कई बार हाथ पैर में इतनी भी जान नहीं होती वह कुछ उठा सके या चल सके। ऐसे लोग पूरी जिंदगी वील चेयर पर ही होते हैं। हुसैन भी इसी तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं।

हार्ट में 3 ब्लॉकेज

डॉक्टर कुमार ने बताया कि हुसैन के हार्ट में तीन ब्लॉकेज पाए गए थे। वह इराक के कई अस्पताल गए लेकिन कोई भी डॉक्टर इलाज करने को तैयार नहीं हुआ क्योंकि हाथ-पैर छोटे होने की वजह से एंजियोप्लास्टी के लिए नस का साइज छोटा पड़ रहा था। आखिरकार वह दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर ने बताया, पहले हमने बाइपास सर्जरी का प्लान किया था लेकिन उनके साइज को देखकर टाल दिया गया। पैर की नस से हार्ट तक पहुंचना भी मुश्किल था, इसलिए हाथ के जरिए उनके हार्ट में पहुंचा गया। यह मुश्किल प्रॉसिजर था, लेकिन सफल रहा।

बचें च्यूइंग गम से

डॉक्टर विवेका कुमार का कहना है कि जो महिलाएं गर्भ के दौरान च्यूइंग गम या पेन किलर ज्यादा खाती हैं, उनके बच्चे में ऐसी बीमारी होने की संभावना ज्यादा रहती है। डॉक्टर कुमार के मुताबिक, ऐसे पदार्थ में टेराटोजेनिक होता है, जो एंब्रियो को नुकसान पहुंचाता है। कुछ ऐसा ही पदार्थ पेन किलर थैलीडोमाइड में भी पाया जाता है, जिसे अब बैन कर दिया गया है। इसकी वजह से जैनेटिक डिसऑर्डर होता है और बच्चा सील सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। महिलाओं को प्रेग्नेंसी के दौरान च्यूइंग गम से बचना चाहिए।

स्वास्थ्य पर 'हार्ड' होते 'सॉफ्ट' ड्रिंक्स के खतरे

सॉफ्ट ड्रिंक्स की आदत बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को है। मौसम चाहे जो हो, इनके दीवाने इन्हें पीकर ही अपनी तलब मिटाते हैं। इससे क्षणिक तौर पर भले ही उन्हें अच्छा महसूस होता हो, पर दीर्घकालिक दृष्टि से ये सेहत के दुश्मन साबित होते हैं। एक दैनिक में छपी रिपोर्ट के अनुसार, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते ही तत्काल उसका प्रभाव शुरू हो जाता है। 20 मिनट में ही ब्लड शूगर का स्तर बहुत हाई हो जाता है। 40 मिनट बाद सॉफ्ट ड्रिंक्स में मौजूद कैफीन शरीर में समा जाती है जो ब्लड प्रैशर को बढ़ा देती है।

इसके कुछ ही समय बाद शरीर में डोपमाइन नामक कैमिकल बनता है जो एक तरह का नशा पैदा करता है। धीरे-धीरे सॉफ्ट ड्रिंक्स एडिक्शन हो जाती है। इसके 15 मिनट बाद शरीर के लिए महत्वपूर्ण कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं। डीहाइड्रेशन की वजह से थकान महसूस होने लगती है। यदि कोई व्यक्ति 350 मिलीलीटर सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल का सेवन करता है तो उसमें इतनी अधिक शक्कर होती है जो एक वयस्क आदमी की दिन भर की जरूरत से अधिक होती है।

फोर्टिस हॉस्पिटल की डा. नीलू तलवार के अनुसार सॉफ्ट ड्रिंक्स में मौजूद कैरेमल शरीर को इंसुलिन विरोधी बना देता है।

इम्पीरियल कालेज लंदन की शोध के अनुसार, सॉफ्ट ड्रिंक्स की हर 350 मिलीलीटर की बोतल के सेवन के साथ टाइप-2 डायबिटीज होने का खतरा 20 प्रतिशत बढ़ जाता है।

अमेरिकी हार्ट एसोसिएशन की शोध के अनुसार दुनिया में हर साल 1 लाख 80 हजार लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स की वजह से मरते हैं।

कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मेलमैन स्कूल आफ पब्लिक हैल्थ ने अपने अध्ययन में पाया कि शीतल पेयों में पाया जाने वाला सोडा बच्चों में आक्रामकता, विरक्ति और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी जैसी समस्याएं पैदा करता है। नियमित रूप से शीतल पेय पीने वाले बच्चे ज्यादा लड़ाई-झगड़ा करते हैं और जल्दी असंयमित हो जाते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स में पोषक तत्वों का नितांत अभाव रहता है। इसमें विटामिन तथा खनिज लवण आदि नहीं होते।

सॉफ्ट ड्रिंक्स की अम्लीयता अधिक होती है जो हमारे दांतों और हड्डियों को गलाने में सक्षम है। हड्डियां गलने लगती हैं और इनका कैल्शियम धमनियों, शिराओं या अंगों में जमा होने लगता है। गुर्दे में जमा होकर यह पथरी का कारण बनता है। आम तौर पर लोग भोजन करने के बाद सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन करते हैं। पेट में उपस्थित पाचक एंजाइमों की कार्यक्षमता 37 डिग्री सैल्सियस तापमान पर सर्वाधिक होती है जबकि सॉफ्ट ड्रिंक्स का तापमान इससे बहुत कम, जीरो डिग्री तक होता है। इस वजह से पाचक रस काम नहीं कर पाते और भोजन अपचा रह जाता है।

ऐसी स्थिति में उसका फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है जिससे गैसें एवं विषैले पदार्थ बनने लगते हैं। आंतें इन्हें सोखकर रक्त में पहुंचा देती हैं और रक्त के साथ शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचकर ये कई प्रकार के रोग पैदा करते हैं। कार्बनडाइआक्साइड शरीर को काफी नुक्सान पहुंचाती है। कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक छात्र एक प्रतियोगिता में सॉफ्ट ड्रिंक्स की आठ बोतलें एक साथ पी गया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई। डाक्टरों ने मृत्यु का कारण उसके रक्त में कार्बनडाइआक्साइड की अत्यधिक मात्रा होना बताया था।

कुछ लोगों को कैमिकल, रंग और सुगंध आदि से एलर्जी होती है। ऐसे में सॉफ्ट ड्रिंक्स में मौजूद रसायन, रंग सुगंध उनके लिए जानलेवा हो सकती है। इसी प्रकार सॉफ्ट ड्रिंक्स को लम्बे समय तक टिकाऊ या सुरक्षित बनाए रखने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं जो निरापद नहीं होते।

कुछ लोग नकली सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने और बेचने का धंधा करते हैं। वे प्रसिद्ध कम्पनियों की खाली बोतलों में नकली या घटिया माल भरकर उपभोक्ता की सेहत और जेब दोनों पर डाका डाल रहे हैं।

गर्मियों में ये 5 तरीके फैट कम करेंगे

फिटनेस के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा जबरदस्त ट्रेनिंग और कार्डियो की ही जरूरत हो। रेग्युलर आउटडोर ऐक्टिविटीज भी एक्स्ट्रा कैलरी कम कर सकती हैं। गर्मियों में आप कुछ ऐसी मजेदार ऐक्टिविटीज अपना सकते हैं जिनके जरिए कैलरी कम की जा सके। जानिए ऐसी पांच गतिविधियां-

स्विमिंग- स्विमिंग पूल में हल्का फुल्का स्विम करना भी आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है। अगर आप ठीक-ठाक समय तक स्विमिंग करते हैं तो कैलरी बर्न होती ही हैं लेकिन यदि हल्की-फुल्की करें तो भी एक हद तक कैलरी बर्न की जा सकती है। बस ये ध्यान रखें कि स्लो पेज पर स्विम करें।

साइकलिंग- साइकलिंग के नाम से बचपन याद आ जाता है। कितना अच्छा हो यदि आप इन गर्मियों में अपने बचपन को याद करते हुए थोड़ी बहुत साइकलिंग भी कर लें। इससे एक पथ दो काज हो जाएंगे. बचपन की मौज की याद ताजा और अच्छी एक्सरसाइज भी।

वाटर स्पोर्ट्स- गर्मियों में पानी में डुबकी लगाने वाले गेम्स न सिर्फ मजा देते है बल्कि आपको कैलरी बर्न करने मे भी मदद करते हैं। वाटर स्कीइंग, वाटर राफ्टिंग जैसे स्पोर्ट्स के जरिए एक्स्ट्रा कैलरीज बर्न करिए।

बैडमिंटन- क्या आपको पता है कि आउटडोर जैसे बैडमिंटन जैसे गेम्स आपको 10 मिनट में 50 कैलरीज से निजात दिला सकते हैं। यह खेल मजेदार तो है ही और इसके लिए आपको कुछ खास तैयारी भी नहीं करनी है। केवल दो रैकेट्स और शटलकॉक्स. और आप हो गए तैयार।

गार्डनिंग- क्या आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं? गर्मी के इस मौसम में अपने गार्डन में कुछ वक्त बिताइए या गार्डन बनाइए। नए प्लांट्स लगाना, उनकी देखभाल करना और मिट्टी आदि से संबंधित जो काम आप करेंगे वह न सिर्फ आपकी कैलरी बर्न करेगा, आपको फ्रेश सब्जियां-फल भी कुछ समय बाद मिलने लगेंगे।

लिवाली के बल पर उछला सेंसेक्स

शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन बढ़त, सेंसेक्स 740 अंक चढ़ा

मुंबई। 12 समूहों में जबरदस्त दिवाली और वैश्विक बाजार के मिलेजुले रुख के बीच बीएसई का सेंसेक्स 740.34 अंक उछलकर 58683.99 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का निफ्टी 172.95 अंक उछलकर 17498.25 अंक पर रहा।

स्थानीय स्तर पर वित्त, इंडस्ट्रियल्स, आईटी, दूरसंचार, ऑटो, बैंकिंग और रियल्टी समेत बारह समूहों में हुई लिवाली की बदौलत शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन भी बढ़त पर रहा। दिग्गज कंपनियों की तरह बीएसई की छोटी और मझौली कंपनियों में भी लिवाली का जोर रहा। इस दौरान मिडकैप 0.78 फीसदी बढ़कर 24,037.80 अंक और स्मॉलकैप 1.09 फीसदी चढ़कर 28,129.47 अंक पर रहा। इस दौरान बीएसई में कुल 3509 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 2121 में तेजी जबकि 1281 में गिरावट रही वहीं 107 में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी तरह एनएसई में 32 कंपनियां हरे जबकि 18 लाल निशान पर रही। बीएसई में वित्त समूह में सबसे अधिक 1.71 प्रतिशत की तेजी जबकि धातु समूह में सबसे अधिक 2.89 प्रतिश्त की गिरावट रही। इसके अलावा सीडीजीएस 1.06, एफएमसीजी 0.58,

इंडस्ट्रियल्स 1.25, आईटी 1.15, दूरसंचार 1.09, ऑटो 1.20, बैंकिंग 1.36, कैपिटल गुड्स 1.14, टेक 0.97 और रियल्टी समूह के शेयर 1.49 फीसदी चढ़े। वैश्विक बाजार में मिलाजुला रुख रहा। इस दौरान ब्रिटेन का एफटीएसई 0.10, हांगकांग का हैंगसैंग 1.39 और चीन का शंघाई कंपोजिट 1.96 प्रतिश्त चढ़ा जबकि जर्मनी का डैक्स 1.35 और जापान का निक्केई 0.80 प्रतिशत लुढ़क गया।

419 अंक मजबूत खुला सेंसेक्स

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 419 अंक की मजबूती के साथ 58,362.85 अंक पर खुला लेकिन बिकवाली के दबाव में 58,176.00 अंक के निचले स्तर तक फिसल गया। लिवाली के बल पर यह लगातार बढ़ता हुआ कारोबार के अंतिम चरण में 58,727.78 अंक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी भी 143 अंक की तेजी लेकर 17,468.15 अंक पर खुला और सत्र के दौरान 17,387.20 अंक न्यूनतम जबकि 17,522.50 अंक के उच्चतम स्तर पर रहा।

एफआईआई की शेयर हिस्सेदारी घट, कुल मूल्य घटकर 582 अरब डॉलर पर

मुंबई। विदेशी कोषों ने घरेलू शेयर बाजार में वित्त वर्ष 2020-21 में 23 अरब डॉलर के रिकॉर्ड अतिरिक्त निवेश के बाद वित्त वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड बिकवाली की, जिससे एनएसई-500 में उनकी हिस्सेदारी घटकर 19.9 प्रतिशत या 582 अरब डॉलर रह गई। विदेशी कोषों की एनएसई-500 में अधिकतम हिस्सेदारी 21.4 प्रतिशत रही है। ब्रोकरेज फर्म बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में इस सप्ताह की शुरुआत तक कुल एफपीआई बाह्य प्रवाह रिकॉर्ड 14.6 अरब डॉलर रहा। इसमें से सिर्फ मार्च में 5.4 अरब अमेरिकी डॉलर की निकासी हुई, जबकि फरवरी में 4.7 अरब डॉलर की निकासी देखी गई थी।

इंडिया रेटिंग्स ने घटाया आर्थिक वृद्धि अनुमान

रूस-यूक्रेन संकट का असर

नई दिल्ली। रेटिंग्स एजेंसी इकरा के बाद क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटा दिया है। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए रेटिंग एजेंसी ने भारत की वृद्धि दर अनुमान को कम किया है।

इंडिया रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि के अपने अनुमान को घटाकर 7.0 से 7.2 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले मंगलवार को रेटिंग इजेंसी इकरा ने भारत के जीडीपी वृद्धि के अनुमान को आठ से घटाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया था। इंडिया रेटिंग्स ने दो तरह की परिस्थितियों को सामने रखकर अलग-अलग अनुमान लगाए हैं। इस एजेंसी की बुधवार को जारी रिपोर्ट में एक अनुमान तेल के दामों के तीन माह तक ऊंचा रहने और दूसरे में छह माह तक ऊंचा रहने की मान्यता के आधार पर है। पहली मान्यता के अनुसार 2022-23 में आर्थिक वृद्धि 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है जबकि दूसरी परिस्थिति में रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि देश की आर्थिक वृद्धि घटकर 7.0 प्रतिशत रह सकती है। एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन दोनों परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार दीर्घकालीन प्रवृति की संभावनाओं की तुलना में क्रमशः 10.6 प्रतिशत और 10.8 प्रतिशत कम रहेगा।

उपभोग की मांग धीमी रही

इंडिया रेटिंग के प्रधान अर्थशास्त्री और निदेशक लोक वित्त सुनील कुमार सिन्हा ने कहा कि निजी पूर्ण उपभोग व्यय पीएफसीसी के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में उपभोग की मांग धीमी रही। यद्यपि वर्ष के दौरान त्योहारी सीजन में कुछ चुनिंदा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में तेजी देखी गयी। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के उपभोक्ता आत्मविश्वास सर्वेक्षण के जनवरी 2022 के चक्र में वर्तमान स्थिति सूचकांक में हल्का सुधार दिखा, लेकिन अब भी यह निराशा के क्षेत्र में बना हुआ है। जनवरी 2022 में कोविड-19 के संक्रमण के फिर बढ़ने से प्रत्याशा सूचकांक में भी नरमी आयी। इंडिया रेटिंग्स का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2022-23 में पीएफसीई में पहले और दूसरे परिदृश्य में क्रमशः 8.1 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत की वृद्धि होगी जबकि पहले इसमें 9.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। एजेंसी का अनुमान है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण जिंसों के भाव में उछाल और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने से बड़ी कंपनियों के उत्साह पर असर पड़ेगा और वे पूंजी निवेश की योजनाओं को टाल सकती हैं।

बाजार में 47 फीसदी बढ़ी नकली दवाएं

नकली दवाओं से मरीजों पर संकट

नई दिल्ली। कोरोना महामारी का अर्थव्यवस्था पर भले ही बुरा असर देखने को मिला है और इससे आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुई हो, लेकिन हेल्थकेयर सेक्टर और इससे जुड़े सेगमेंट खासकर दवाओं व अन्य मेडिकल उत्पादों का बाजार तेजी से बढ़ा है। लोगों ने इस मौके का भी दुरुपयोग करने में कोई असर नहीं रहने दी। इसका अंदाजा एक हालिया रिपोर्ट से लग जाता है, जिसमें बताया गया है कि पिछले साल नकली दवाओं व मेडिकल उत्पादों के चलन में करीब 47 फीसदी की तेजी आई।

नक्कालों के खिलाफ लोगों को जागरूक बनाने वाले गैर लाभकारी संगठन ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन, एएसपीए की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, साल 2020 की तुलना में 2021 में घटिया क्वालिटी वाले और नकली मेडिकल उत्पादों के मामले 47 फीसदी बढ़ गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नकली दवाओं के जो मामले सामने आए, उनमें से ज्यादातर कोविड19 से संबंधित रहे। इनमें वैक्सीन, दवाएं, कोविड टेस्ट किट, एंटीबॉयोटिक, फेस मास्क और सेनेटाइजर आदि शामिल रहे।

23 राज्यों में नकली दवाओं के मामले सामने आए

एएसपीए की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल जब देश में कोविड की दूसरी लहर का चरम चल रहा था, तब 29 राज्यों व 7 केंद्रशासित प्रदेशों में से 23 राज्यों में नकली दवाओं के मामले सामने आए। संगठन के प्रेसीडेंट नकुल पशरीचा का इस बारे में कहना है, अपराधियों ने लोगों की जरूरत का फायदा उठाते हुए ज्यादा से ज्यादा नकली मेडिकल प्रॉडक्ट के बचने के लिए महामारी की आपदा को अवसर के रूप में लिया। कोविड19 महामारी से लड़ाई में इन नकली दवाओं व अन्य मेडिकल उत्पादों का कितना बुरा असर पड़ा, यह ऑलमोस्ट अननोटिस्ड रह गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराधी असली दिखने वाली पैकेजिंग में इस तरह से नकली दवाएं बना रहे हैं, जिसे पहचान पाना मुश्किल है। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि इस अपराध पर लगाम लगाई जाए।

आईएलएंडएफएस ने किया 61000 करोड़ रुपए कर्ज का निपटान

मुंबई। गैर बैंकिंग कंपनी आईएलएंडएफएस ने अपना कुल कर्ज का निपटान कर दिया है। आईएलएंडएफएस बुनियादी ढांचे के लिये कर्ज देने वाली कंपनी है। प्रबंधन ने 61000 करोड़ रुपए के कर्ज के समाधान की घोषणा की है। यह 347 इकाइयों के समूह पर कुल बकाया 99355 करोड़ रुपए का 62 प्रतिशत है।

सरकार की पहल पर उदय कोटक की अध्यक्षता में आईएलएंडएफएस के नये निदेशक मंडल के गठन के साढ़े तीन साल बाद कंपनी ने कर्ज के बड़े हिस्से के निपटान का ऐलान किया है। कोटक ने दो अप्रैल से छह सदस्यीय बोर्ड के चेयरमैन पद पर अपना कार्यकाल समाप्त होने की भी घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि प्रबंध निदेशक सीएस राजन छह महीने के लिये चेयरमैन पद की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। कोटक ने आईएलएंडएफएस पर बैंकों और अन्य इकाइयों के कुल बकाया में से 61000 करोड़ रुपए यानी 62 प्रतिशत के निपटान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 29 मार्च तक की स्थिति के अनुसार संपत्तियों की बिक्री के जरिये कुल 55000 करोड़ रुपए के कर्ज का समाधान किया गया। कुल 347 इकाइयों में से 248 के मामलों का समाधान हो गया है। कोटक ने कहा कि 101 इकाइयों में से कुछ बंद पड़ी हैं। और केवल सरकार ही उनके बारे में निर्णय कर सकती है।

दोगुना से अधिक होंगी गैस कीमतें

रिलायंस इंडस्ट्रीज व ओएनजीसी जैसी कंपनियों को होगा फायदा

नई दिल्ली। इस सप्ताह गैस की कीमत दोगुना से अधिक बढ़ सकती हैं। इससे गैस उत्पादक रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी जैसी कंपनियों को फायदा होगा।

रिलायंस इंडस्ट्रीज को केजी गैस के लिये 10 डॉलर प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट मिलने की उम्मीद है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी को मुंबई हाई और अन्य क्षेत्रों के लिये दोगुना से अधिक कीमत प्राप्त हो सकती है। सरकार की तरफ से देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमत की समीक्षा एक अप्रैल को होनी है। पिछले साल ऊर्जा के दाम में वृद्धि को देखते हुए ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी को नामांकन आधार पर दिये गये फील्डों से उत्पादित गैस का दाम बढ़कर 5.93 डॉलर प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट हो जाने की संभावना है जो फिलहाल 2.9 डॉलर यूनिट है। मामले से जुड़े दो सूत्रों के अनुसार, वहीं रिलायंस और उसकी

परिचालित डी6 जैसे कठिन स्थिति वाले ब्लॉक के लिये दाम 9.9 से 10.1 डॉलर प्रति यूनिट हो सकता है, जो फिलहाल 6.13 डॉलर प्रति यूनिट है। रिलायंस-बीपी परिचालित केजी क्षेत्रों को कठिन फील्ड की श्रेणी में रखा जाता है। ये दरें नियमित क्षेत्रों ओएनजीसी की मुंबई तटीय क्षेत्र में बसई फील्ड और केजी बेसिन जैसे मुक्त बाजार क्षेत्रों के लिये अबतक की सबसे ऊंची कीमत है। साथ ही अप्रैल, 2019 के बाद यह दूसरा मौका है जब दरें बढ़ेंगी और यह वृद्धि ऐसे समय हो रही है, जब मानक अंतरराष्ट्रीय

एक अप्रैल हो होंगी दरें निर्धारित

सरकार हर छह महीने पर एक अप्रैल और एक अक्टूबर को दरें निर्धारित करती है। यह निर्धारण अमेरिका, कनाडा और रूस जैसे अधिशेष गैस वाले देशों में जारी सालाना औसत कीमतों के आधार पर होता है। इसमें एक तिमाही का अंतर होता है। यानी एक अप्रैल से 30 सितंबर की कीमतें जनवरी, 2021 से दिसंबर, 2021 के औसत मूल्य के आधार पर होगी। और इस दौरान दरें ऊंची रही हैं।

छह साल में पहली बार उत्पादकों को होगा फायदा

सूत्रों ने कहा कि गैस के दाम बढ़ने से सीएनजी और पाइप के जरिये घरों में जाने वाली रसोई गैस पीएनजी के दाम बढ़ सकते हैं। वहीं उत्पादकों के लिये छह साल में पहला

निवेश योजना के नियमों में संशोधन

नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने सामूहिक निवेश योजनाओं के नियमों को कड़ा करते हुए संशोधन किया है। इन योजनाओं का संचालन करने वाली इकाइयों के लिए न्यूनतम नेटवर्थ की जरूरत को बढ़ाया गया है। साथ ही ऐसी योजनाओं का संचालन सिर्फ उन इकाइयों को करने की अनुमति दी जाएगी जिनका पिछला रिकॉर्ड अच्छा है। नियामक ने प्रतिभूतियों के स्वामित्व के स्थानांतरण को सुगम करने सूचीबद्धता और खुलासा अनिवार्यता से संबंधित नियमनों में बदलाव की भी मंजूरी दी है। साथ ही सेबी ने म्यूचुअल फंड के चांदी के एक्सचेंज ट्रेडेड कोष ईटीएफ के पास मौजूद चांदी उत्पादों के लिए संरक्षण सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देने नियमन में बदलाव को मंजूरी दी है। निवेशकों को धन जुटाने के जरिये चूना लगाने की घटनाओं के मद्देनजर सेबी ने निवेश प्रबंधन कंपनी सीआईएमसी और उसके सहायक, शेयरधारकों की किसी योजना में हिस्सेदारी को 10 प्रतिशत पर फैसला किया है।

बाजार समीक्षा कपास आपूर्ति घटने से तमाम कपड़ा मिलें बंदी की कगार पर

कॉटन महंगा होने से कपड़ा उद्योग दुविधा में

इंदौर। देश-विदेश में कॉटन के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर जा पहुंचे है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल इसमें राहत मिलने की संभावना काफी कम नजर आ रही है। कॉटन महंगा होने से कपड़ा उद्योग न केवल परेशान हो रहा है, बल्कि दुविधा बढ़ती जा रही है।

दरअसल, अच्छी किस्म के कपास के दाम 10-11 हजार रु क्विंटल पहुंच चुके है। इस वजह से सूती धागे की कीमतों में भी भारी घट-बढ़ हो रही है, इसका गार्मेंट उद्योग पर बुरा असर पड़ रहा है। चीन में लॉकडाउन होने से वहां से गार्मेंट निर्यात बाधित होने का लाभ भी भारत के परिधान उद्योग को नहीं मिल पा रहा है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले संकर-6 कपास की कीमत बढ़कर 90000 रु प्रति खंडी (356 किलो) पर पहुंच गई है, जो जनवरी 2021 में करीब 46000 रु थी। यदि, मौजूदा कीमत में लॉजिस्टिक्स लागत भी जोड़ लें, तो इसकी कीमत 1 लाख रु प्रति खंडी होती है, जबकि कुछ श्रेणियों की कीमत पहले ही इस स्तर को छू चुकी है। उद्योग संगठनों का आरोप है कि कपास का स्टॉक बिक्री के बजाय अटकलबाजी में रोक लिया गया है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि इसके दाम और ऊपर पहुंचेंगे। अगर प्रति खंडी कॉटन की कीमत में 1000 रु बढ़ती है तो काटन यार्न (धागे) के दाम 4 रु किलो बढ़ जाती है। कपड़ा उद्यमी ने बताया की कच्चा कपास पिछले साल से 40 प्रतिशत बढ़कर सर्वोच्च स्तर पर है। इससे पूरा उद्योग परेशान है और छोटे कारोबारी तबाह हो रहे हैं। उद्योग संगठनों ने इस मसले पर सरकार के हस्तक्षेप की मांग की है।अक्टूबर 2021 से शुरू सत्र में कपास की कीमत दोगुनी हो गई हैं। बहरहाल कपास उपलब्धता प्रभावित है। यहां तक कि जब मिलें ज्यादा दाम देने को तैयार हैं, लेकिन गुणवत्तायुक्त माल की आपूर्ति जटिल है। इससे तमाम मिलें बंदी के कगार पर हैं।

तेल प्लांटों की मांग घटने से सोयाबीन के दाम दबे

इंदौर। सोयाबीन की सीमित आवक के बावजूद तेल प्लांटों की मांग कम होने से बुधवार को दाम मंदे रहे। देश में सरसों की आवक 5.70 लाख बोरी हुई। जयपुर में तेल कंडीशन वाली सरसों 7100-7125 रु पर मजबूत थी। मलेशिया पाम तेल वायदा 1700 डॉलर प्रति टन था। केएलसीई 93 रिंगिट नीची बंद हुई। शिकागो सोया तेल वायदा रनिंग में 46 सेंट ऊंचा चल रहा था। खाद्य तेल प्रति10 किलो के सौदो में सोया रिफाइंड 1505-1510, साल्वेंट 1470-1475, मुंबई रिफाइंड 1475, मूंगफली तेल इंदौर 1600-1620, मुंबई 1620, गुजरात 1600, पामतेल मुंबई 1445, इंदौर 1540, कॉटन तेल 1525 रु था। प्लांट डिलीवरी सौदो में सोयाबीन प्रेस्टीज 7700, अंबिका जावरा 7800, धानुका 7852, एमएस नीमच 7850, रूचि 7725, अवि 7700, महाकाली 7750, कृति 7700, प्रकाश 7750, इटारसी 7600, बेतूल 7800 रु क्विंटल के दाम थे। **कपास्या खली सामान्य:** बुधवार को कपास्या खली के दाम अपरिवर्तनीय रहे। खली प्रति 60 किलो के सौदो में इंदौर 2325, देवास-उज्जैन 2330, खंडवा बुरहानपुर 2300-2305 व अकोला कपास्या खली 3425 रु क्विंटल थी।

रत्नाभूषण निर्यात लक्ष्य 100 अरब डॉलर का हो: गोयल

दुबई। वाणिज्य-उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रत्न-आभूषण निर्यातकों से आगामी वर्षों में सालाना 100 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में निर्यात की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने आग्रह किया कि वे बेहतर विपणन उपकरण और डिजाइन के जरिये निर्यात बढ़ाएं। देश के 400 अरब डॉलर के निर्यात में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 10 फीसदी है। जीजेईपीसी के अध्यक्ष कॉलिन शाह ने कहा कि यूएई में हमारा निर्यात बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में हम इसे दोगुना या तिगुना करने के लिए काम करेंगे। गोयल ने दुबई में द इंडिया ज्वेलरी एवयोजिशन (आईजेईएक्स) केंद्र के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे।

महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन 117.50 लाख टन के पार

मुंबई। महाराष्ट्र में गन्ना पेराई अंतिम चरण में है, और चीनी मिलें बंद होना शुरू हो चुकी है। चीनी उत्पादन के मामले में इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे है। महाराष्ट्र के चीनी आयुक्तालय के मुताबिक 29 मार्च 2022 तक राज्य में 27 चीनी मिलों ने पेराई बंद कर दी है। राज्य में चालू सीजन 2021-22 के तहत 29 मार्च तक कुल मिलाकर 197 चीनी मिलों ने गन्ना पेराई में हिस्सा लिया। जिसमे 98 सहकारी एवं 99 निजी चीनी मिलें शामिल थी। इ मिलों द्वारा करीब 1131.91 लाख टन गन्ने की पेराई पूर्ण की जा चुकी है। इससे राज्य में गत दिवस तक 1175.99 लाख क्विंटल (117.76 लाख टन) चीनी का उत्पादन दर्ज किया गया है। राज्य में फिलहाल औसत चीनी रिकवरी 10.39 प्रतिशत बैठ रही है।

डॉलर चना फिर घटा, मूग मोगर में तेजी

इंदौर। सरकार ने उड़द-तुवर का आयात 31 मार्च 2023 तक मुक्त श्रेणी में कर दिया। इससे कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। मंडी में डॉलर चना करीब 6000 बोरी आवक के बीच मामूली घटकर मंडी में 8500-9200, हल्का 7800-8200, निर्यात सौदो में 42-44 काउंट 9900 44-46 काउंट 9800, 58-60 काउंट 8800रह गया। चना कांटा 5050-5100, विशाल 4800-4850, मसूर 6700-6725, उड़द 6500-6800, बेस्ट 7000, एवरेज 5500-6200, मूंग 7000-7300, एवरेज 6500-6700, तुवर 5500-6200, महाराष्ट 6350-6500, कर्नाटक 6650-6700 रु थी।

दाल-चावल के भाव

दालें-चना दाल 6000-6500, तुवर दाल 8200-8800, नई 9100-9800, मसूर दाल 8000-8300, मूंग दाल 8700-9100, मोगर 9300-9600, उडद दाल 8000-8300, मोगर 9100-9500 रु। **चावल**- दयालदास अजित कुमार- बासमती (921) 10000-11000, तिबार 8000-8500, दुबार 7000-7500, मिनी 6500-7000, मोगरा 3500-6000, सैला 6500-9000, कालीमूंछ डिनरकिंग 7500, राजभोग 6500, दूबराज 3500-4000, परमल 2500-2650 हंसा सैला 2450-2650 हंसा सफेद 2350-2450 रु था।

गेहूं: कांडला डिलीवरी 5 दिन में 250 रु घटा

इंदौर। गेहूं की कीमतों में बारी गिरावट के चलते कांडला डिलीवरी सौदो में मात्र 5 दिन में दाम 2500 रु से 250 रु क्विंटल गिरकर 2250 रु के रह गए। इसका असर मंडियों में भी मंदी के रूप में धि रहा है। इंदौर की दोनों मंडियों में करीब 19-20 हजार बोरी आवक दर्ज हुई। मक्का की आपूर्ति सीमित होने से दाम मजबूत थे।

छावनी मंडी में बुधवार को गेहूं मिल क्वालिटी 2000-2050, पूर्णा 2150-2250 लोकवन 2175-2275, मालवराज 2050-2100, शरबती 3300-3450 रु। मिल डिलीवरी सौदो में गेहूं इंदौर देवास, पीथमपुर 2100-2140, जलगांव, अमलनेर, धुलिया 2200 पुणे 2400-2450, मुंबई 2450, बैगलुरू 2650, कांडला डिलीवरी गेहूं 2250, मुंबई पोर्ट डिलीवरी 2280 रु क्विंटल के बताए गए। मक्का की सीमित आपूर्ति के बीच स्टार्च तथा

पोल्ट्री वालों की खरीद से कीमतों में मजबूती बनी हुई है। मंडी में मक्का के दाम 2250-2275, डिलीवरी में मक्का इंदौर 2350-2360, तिरूपति स्टॉर्च घाटाबिल्लोद 2350, बदनावर 2320, मंदसौर राजाराम 2400, पंजाब लाईन मक्का 2600-2625, हरियाणा लाईन 2575-2600 रु प्रति क्विंटल थे।

स्वर्ण आभूषण विक्रेताओं की आय में होगा इजाफा

नई दिल्ली। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने बुधवार को कहा कि स्थिर मांग व लगातार ऊंची कीमतों के चलते स्वर्ण आभूषणों के खुदरा विक्रेताओं की आय वित्तवर्ष 2022-23 में 12 से 15 प्रतिशत बढ़ सकती है। क्रिसिल के अनुसार सोने की ऊंची कीमतों और बेहतर परिचालन लाभ के कारण वित्त वर्ष 2022-23 में वार्षिक आधार पर परिचालन मार्जिन में 0.5 से 0.7 प्रतिशत का सुधार हो सकता है और यह 7.3 से 7.5 प्रतिशत तक रहेगा। उच्च पूंजीगत व्यय के बावजूद अगले वित्त वर्ष में संगठित आभूषण उद्योग के लिए ऋण परिदृश्य स्थिर रहेगा। वहीं अगले वित्त वर्ष के दौरान आभूषणों की मांग स्थिर रहेगी।

चीनी उद्योग द्वारा एथेनॉल खरीद समझौतों पर भेदभाव का आरोप

नई दिल्ली। चीनी उद्योग ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) स्थापित चीनी मिलों और सरकार की रियायती ऋण योजना का हिस्सा नहीं बनने वालों के साथ एथनॉल खरीद के दीर्घकालिक अनुबंध करने से हिचकिचा रही हैं।

मिलों ने कुछ दिन पहले केंद्रीय खाद्य और पेट्रोलियम सचिवों को लिखे पत्र में कहा था, कि जब तक ओएमसी खरीद योजनाओं में सुधार नहीं कर लेतीं, तब तक चीनी मिलों द्वारा अपनी एथनॉल विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण निवेश पर सवाल खड़ा रहेगा, जिससे वर्ष 2025 तक 20 प्रतिशत के मिश्रण का लक्ष्य प्रभावित हो सकता है। जानकारियों के मुताबिक इन तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि एथनॉल की आपूर्ति के लिए अनुबंध देने की खातिर कोई तरजीह नहीं है, तथा नीति के तहत एथेनॉल आपूर्ति मिश्रण का रुख गन्ने से अनाज की ओर मोडने का इरादा है।

कच्चा तेल वायदा में मजबूती

नई दिल्ली। फिजिकल मांग बढ़ने के बीच वायदा कारोबारियों द्वारा सौदे बढ़ाने से बुधवार को कच्चे तेल वायदे में मजबूती रही। एमसीएक्स पर अप्रैल अनुबंध 156 रु. (1.97 फीसदी) बढ़कर 8066 रु प्रति बैरल हो गया। इसमें 6130 लॉट के सौदो हुए। विश्लेषकों ने कहा कि वायदा सौदों का आकार बढने से यह तेजी आई। वैश्विक स्तर पर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चा तेल 2.02 प्रतिशत बढ़कर106.35 डॉलर प्रति बैरल था। न्यूयॉर्क में ब्रेंट कच्चा तेल बढ़कर112.10 डॉलर पर पहुंच गया।

ग्लोबल कीमतों में बढ़त से सोना-चांदी सुधरे

इंदौर। बुधवार को ग्लोबल मार्केट में दाम बढ़ने का असर घरेलू सराफा बाजारों में भी दिखा। इससे सोना-चादी के भाव में सुधार रहा। कॉमेक्स पर सोना ऊंचे में 1934, नीचे में 1917.9 डॉलर पर 9.10 डॉलर प्रति औंस ऊंचा चल रहा था। वहीं चांदी ऊंचे में 2510, नीचे में 2475 सेंट के दायरे में 15 सेंट ऊंची बताई जा रही थी। **इंदौर सराफा-** सोना कैश में टंच 52000, कैडबरी 51900, आरटीजीएस 52300 रु प्रति 10 ग्राम, चांदी कैश में टंच 67600 चौरसा 67500, आरटीजीएस में 68300 रु प्रति किलो थी। **रतलाम-** आरटीजीएस सोना 52850 एवं चांदी 68300 रु थी। **उज्जैन-** सोना 52100, चांदी प्रति किलो 67900 रु थी।

वैश्विक सराफा

विवरण	सोना	चांदी
ऊंचे में	1934.00	25.10
नीचे में	1917.90	24.76
रनिंग में	1930.10	24.99

कालीमिर्च 2 दिन में 8 रु किलो बढ़ी

इंदौर। कालीमिर्च के नीचे दामों पर बिक्री अटकने और खरीदी बढ़ने से दाम मजबूत थे। बुधवार को दाम 5 रु किलो ऊंचे बताए गए। इस तरह दो दिन में दाम 8 रु किलो बढ़ गए है। पिस्ता की आपूर्ति में कमी के बीच दाम 20-25 रु किलो ऊंचे बोले जा रहे थे। शकर के व्यापारियों को अप्रैल के मासिक कोटा जारी होने का इंतजार है, क्योंकि इसी के बाद बाजार में तेजी-मंदी की चाल निर्भर होगी। हल्दी की नई आवक बढ़ रही है।

शकर 3480-3500, सुपर 3520-3540, एम 3650-3675, गुड़ 2850-4000, कालीमिर्च कालामोती 534 ,दीपक 548, गणेश 567, मटरदाना 582, जीरा पंजा 243 खुशबू 245 सुपर 250-260, हल्दी सांगली 165-166, निजामाबाद 110-130, नारियल प्रति बोरी 120 भर्ती 1750-1800, 160 भर्ती 1750-1800, 200 भर्ती 1900-1950, 250 भर्ती 2200-2250, खोपरा गोला 195-215, खोपराबूरा 15 किलो 2400-4400, साबूदाना 4350-4700, वरलक्ष्मी 5050, ग्लास 5550, वरलक्ष्मी 1 किलो पैक 5750, सौंफ 150-210, हल्की 121-135, लौंग 675-750, दालचीनी 285-295, जायफल 750-850, जावत्री 1950-2100, बड़ी इलायची 725-850,

इलायची एक्स्ट्रा बोल्ड 1800-1850, बोल्ड 1650-1700 मध्यम 1550-1600, मिनी 1400-1500, पानपट्टी 1300-1400, पोस्ता 1500-1750, काजू (240) 770-790, (320) 690-705, डब्ल्यू वन (300) 670-680, एस एस डब्ल्यू 630-650, जेएच 620-630, टुकड़ी 600-650, बादाम इनडिपेंटेड 580-600, अमेरिकी 620-625, आस्ट्रेलियन 640-650, टांच 540-560, किशमिश 375-550, इंडियन 180-230, मखाना 450-800, पिस्ता 1450-1575, नमकीन 870-950 रु। **आटा-मैदा** (50 किलो) आटा 1350-1370, मैदा 1400-1410, रवा 1440-1450, बेसन 3325-3350 रु।

अंचल की मंडी

छावनी किसानी मंडी में 16374 क्विंटल आवक

इंदौर। संयोगितागंज स्थित छावनी किसानी मंडी में बुधवार को कुल मिलाकर 16374 क्विंटल कृषि उपज की आवक दर्ज हुई। इसमें गेहूं 8901, सोयाबीन 853, डॉलर चना 5164, चना 1034, मूंग 13, मिर्च 367, हरा चना 10 बोरी शामिल था। नीलामी के दौरान भाव-सरसों 6295, सोयाबीन 3000-7595, गेहूं 1930-2500, मक्का 1950-2002, डॉलर चना 3995-9225, चना 3000-5645, मूंग 6895, तुवर 5500-5800, उड़द 3505, धनिया 7000-10000, मिर्च 4000-15030, मैथी 3905, हरा चना 8305 रु क्विंटल था। मंडी 31 मार्च के दिन बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी एवं 1 अप्रैल शुक्रवार को अमावस्या तथा 2 अप्रैल शनिवार को गुड़ी पडवा, चेटीचंड, 3 अप्रैल को रविवार के साप्ताहिक अवकाश पर नीलामी कार्य बंद रहेगा।

भीकनगांव- मंडी में कपास 35 वाहन, 33 बैलगाड़ी आवक हुआ। इसके अलावा गेहूं 9200 सोयाबीन 1026, मक्का 811, तुवर 53, चना 1271 बोरी आवक हुआ। नीलामी के दौरान भाव इस प्रकार थे-कपास 9801-12400, गेहूं 1900-2300, सोयाबीन 6201-7550 मक्का 1700-2200, तुवर 5221-6300, चना 4344-4910 रुपए क्विंटल। **खंडवा-** स्थानीय मंडी में कपास की आवक 21 वाहन दर्ज हुई। मंडी में 31 मार्च से 3 अप्रैल तक नीलामी कार्य बंद रहेगा। भाव-कपास 7861-11500, गेहूं 1981-2257, सोयाबीन 4600-8977, तुवर 4700-6201, चना 4359-4778, मक्का 1991-2076, उडद 00 रु क्विंटल था। **महू-** सोयाबीन 5715-7718, चना 4001-4680, बिटकी चना 4120-5192, डॉलर चना 6801-8041, गेहूं 1870-2458, मक्का 1771 रु। **खेतिया-** मंडी में कपास 27 वाहन 3 बैलगाड़ी, मक्का 10 वाहन व गेहूं 6 वाहन आवक

सार समाचार

रूस ने तालिबान की ओर से नियुक्त पहले राजनयिक को मान्यता प्रदान की

मास्को । रूस ने अफगानिस्तान में काबिज तालिबान सरकार की ओर से नियुक्त पहले राजनयिक को मान्यता दे दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार द्वारा नियुक्त पहले राजनयिक को रूस की ओर से मान्यता दे दी गई है। सर्गेई ने चीन के तुंशी में अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के विदेश मंत्रियों की तीसरी बैठक को संबोधित करते हुए कहा, 'मैं यह बताना चाहूंगा कि नए अधिकारियों द्वारा भेजे गए पहले अफगान राजनयिक, जो पिछले महीने मॉस्को पहुंचे, को हमारे मंत्रालय ने मान्यता प्रदान कर दी है।' साथ ही उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सीमा से लगे देशों में अमेरिकी या उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) सैनिकों की मौजूदगी स्वीकार्य नहीं है। रूसी समाचार एजेंसी ने लावरोव के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा, रजैसा कि हमने पहले ही कहा है, हम मुख्य रूप से मध्य एशिया में अमेरिका और नाटो के किसी भी सैन्य बुनियादी ढांचे की तैनाती को अस्वीकार करते हैं।" उन्होंने कहा, रअमेरिका अफगानिस्तान के नागरिकों और शरणार्थियों के भविष्य की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और वश्विक बैंक में अपने प्रभाव के माध्यम से अफगानिस्तान में सामाजिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बाधा डाल रहा है।र उल्लेखनीय है कि लावरोव दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को भारत पहुंचेंगे। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान की शुरूआत के बाद श्री लावरोव का यह पहला भारत दौरा है। उधर, ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस भी भारत पहुंच रही हैं।

श्रीलंका में हालात बहुत खराब, चीन,दुध, चावल की कमी, दवाईयों की कमी से सर्जरी रोकी गई

बिजली की कटौती 10 घंटे रोजाना

कोलंबो । श्रीलंका में अभी तक का सबसे बड़ा पावर कट शुरू हो गया है। आजादी के बाद अब तक के सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में प्रतिदिन 10 घंटे की बिजली कटौती की शुरूआत हो गई है। देश में पेट्रोलियम ईंधन की भारी कमी है, इसकारण बिजली का उत्पादन काफी कम हो गया है। देश में खाने-पीने का सभी जरूरी सामानों की भारी कमी है, इससे गुस्साए लोग गोटाबाया राजपक्षे सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। यही हाल दवा की दुकानों और अस्पतालों का भी है। दवाओं की कमी के चलते सर्जरी रोकी जा रही है, जिससे कई मरीजों की जान जाने का खतरा भी बढ़ गया है। श्रीलंका के बिजली बोर्ड ने कहा कि महीने की शुरूआत से सात घंटे की जो बिजली काटी जा रही थी, अब उस 10 घंटे किया जा रहा है क्योंकि बिजली उत्पादन के लिए ईंधन नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि श्रीलंका की 40 प्रतिशत से अधिक बिजली हाइड्रोपावर से पैदा होती है। ईंधन की कमी है, साथ ही बारिश न होने से अधिकांश नदियों और जलाशयों में पानी नहीं है जिस कारण बिजली पैदा करना और कठिन हो रहा है। श्रीलंका में अधिकांश बिजली उत्पादन कोयले और तेल से होता है। इन दोनों ही चीजों के लिए श्रीलंका आयात पर निर्भर है लेकिन देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली है, इस कारण सभी जरूरी चीजों के साथ-साथ इनका आयात भी नहीं हो पा रहा है। इस बीच सरकार के स्वामित्व वाली खुदरा ईंधन विक्रेता कंपनी सीलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (सीपीसी) ने कहा कि देश में कम से कम दो दिनों तक डीजल नहीं रहेगा। सीपीसी ने पेट्रोल स्टेशनों पर लंबी कतारों में तेल का इंतजार कर रहे वाहन चालकों से कहा है कि वहां अपने घरों को लौट जाएं और ईंधन की आपूर्ति होने के बाद यहां आएं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी साल की शुरूआत से ही भारी वृद्धि हुई है। अब तक पेट्रोल की कीमतों में 92 फीसद और डीजल की कीमत में 76 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि खाना बनाने के गैस और मिट्टी के तेल को खरीदने के लिए सरकार को पैसे जुटाने में 12 दिन लग गए। सरकार ने बताया 44 करोड़ डॉलर की राशि किसी तरह जुटाई जिसके बाद इन चीजों को आयात किया जा सका। श्रीलंका पर भारी विदेशी कर्ज है, इसकारण मार्च 2020 में सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। श्रीलंका को तब 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज चुकाना था। इसके बाद श्रीलंका में सभी आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो गई और कीमतों में तेजी से उछाल आया। श्रीलंका में चावल, चीनी, दूध जैसे सभी आवश्यक सामानों की कमी हो गई है। जो सामान दुकानों पर उपलब्ध हैं, उनकी कीमत देखकर लोग उन्हें खरीद नहीं पा रहे हैं। इसके बाद श्रीलंका में पलायन भी शुरू हो गया है। लोग अपने देश को छोड़कर पड़ोसी भारत का रुख कर रहे हैं। श्रीलंका में आवश्यक दवाइयों और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते कई अस्पतालों में सर्जरी रोक दी गई है। श्रीलंका की आर्थिक दशा पर बात करते हुए महिला ने बताया कि उनके पति खाड़ी देश में रहते हैं और अगर उन्हें जाने का मौका मिला,तब वहां अवश्य ही श्रीलंका छोड़ देंगी। महिला बताती हैं कि तीन सदस्यों के उनके परिवार का एक महीने का खर्च पहले 30 हजार श्रीलंकाई रुपये आता था लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है। वहां गुस्साए अंदाज में कहती हैं, 'इस महीने मैं पहले ही 83 हजार रुपये खर्च कर चुकी हूं। दूध की कमी है....चावल, दाल के लिए लड़ना पड़ रहा है। बिजली अधिकतर समय गायब ही रहती है, इसके बाद मोमबत्ती भी नहीं मिल रही। पैरासिटामोल की 10 से 12 पत्ती की गोली के लिए 420 से 450 रुपये देने पड़ रहे हैं और कई दवाइयां मिल ही नहीं रहीं। मेरी सैलरी 55 हजार है और मेरे पति जो पैसे भेजते हैं, उनमें हम अपना खर्च चला सकते हैं। लेकिन सामान नहीं मिल रहे। क्या हम पैसे खाकर जिंदा रह सकते हैं?'

रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के शीघ्र बाद हुए साइबर हमले से यूरोप के हजारों लोग प्रभावित हुए

मॉस्को। यूक्रेन पर रूसी हमला शुरू होने के शीघ्र बाद यूक्रेनी सरकार और सैन्य एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सेटेलाइट नेटवर्क पर हुए साइबर हमले के कारण यूरोपीय देशों के हजारों लोगों के ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन प्रभावित हुए थे। उपग्रह (सेटेलाइट) के स्वामित्व वाली कंपनी ने बुधवार को यह खुलासा किया। अमेरिका की कंपनी वायासेट ने इस बात का भी खुलासा किया कि किस तरह साइबर हमले को अंजाम दिया गया, जो अब तक किसी भी युद्ध के दौरान किया गया सबसे बड़ा साइबर हमला है। कंपनी ने इस हमले के व्यापक प्रभाव के बारे में भी जानकारी साझा की है। कंपनी के मुताबिक, इस हमले के कारण पोलैंड से लेकर फ्रांसतक के इंटरनेट उपभोक्ता प्रभावित हुए। हालांकि, कंपनी ने अपने बयान में इस बात की जानकारी साझा नहीं की कि इस हमले के लिए कौन जिम्मेदार था। जबकि, यूक्रेन के अधिकारियों ने रूसी हैकरों पर साइबर हमले को अंजाम देने का आरोप लगाया है।

यूक्रेन को 50 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त मदद देगा अमेरिका

–राष्ट्रपति बाइडन ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से 55 मिनट तक फोन पर बात की

वाशिंगटन। अमेरिका ने रूसी सेना के हमलों का सामना कर रहे यूक्रेन को 50 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त मदद देने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से 55 मिनट तक फोन पर बातचीत की। इस दौरान बाइडन ने उनसे कहा कि (यूक्रेन को) अतिरिक्त मदद जल्द पहुंचायी जाएगी। व्हाइट हाउस के अनुसार, दोनों नेताओं ने यूक्रेन को पहले से दी जा रही सुरक्षा सहायता और हालात के बारे में चर्चा की। जेलेंस्की ने बाइडन प्रशासन और अन्य पश्चिमी देशों से यूक्रेन को सैन्य लड़ाकू विमान प्रदान करने का आग्रह किया है।

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अल्जीरिया में दूतावास में दूतावास के कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ बैठक के दौरान।

14 अप्रैल को 'राष्ट्रीय सिख दिवस' घोषित करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्ताव पेश

वॉशिंगटन । अमेरिका की राजनीति में भारतीय सिखों का लगातार वर्चस्व बढ़ रहा है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति सहित 12 से अधिक सांसदों ने 14 अप्रैल को 'राष्ट्रीय सिख दिवस' घोषित करने को लेकर प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश किया है। अमेरिका के विकास में सिख समुदाय के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करते हुए प्रस्ताव में अमेरिका को सशक्त बनाने और यहां के नागरिकों को प्रेरित करने में सिख समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के तौर पर 'राष्ट्रीय सिख दिवस' घोषित करने का समर्थन किया गया है। सांसद मैरी गेल सानलोन 28 मार्च को सदन में पेश किये गये प्रस्ताव की प्रस्तावक हैं, जबकि कैरेन बास, पॉल टोंको, ब्रायन के. फित्जपैट्रिक, डेनियल म्यूजर, एरिक स्वालवेल, राजा कृष्णमूर्ति, डोनाल्ड नॉरक्रॉस, एंडी किम, जॉन गारामेंडी, रिचर्ड ई नील, ब्रैंडन एफ। बॉयले और डेविड जी वालादाओ इसके सह-प्रस्तावक हैं। सिख कॉकस कमेटी, सिख को-ऑर्डिनेशन कमेटी और अमेरिकन सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एजीपीसी) ने प्रस्ताव का स्वागत किया है।वॉशिंगटन (ईएमएस)। अमेरिका की राजनीति में भारतीय सिखों का लगातार वर्चस्व बढ़ रहा है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति सहित 12 से अधिक सांसदों ने 14 अप्रैल को 'राष्ट्रीय सिख दिवस' घोषित करने को लेकर प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश किया है। अमेरिका के विकास में सिख समुदाय के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करते हुए प्रस्ताव में अमेरिका को सशक्त बनाने और यहां के नागरिकों को प्रेरित करने में सिख समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के तौर पर 'राष्ट्रीय सिख दिवस' घोषित करने का समर्थन किया गया है।

कुर्सी बचाने के लिए इमरान को मिली तीन दिन की मोहलत, पाकिस्तान नेशनल असेंबली 3 अप्रैल तक स्थगित

इस्लामाबाद। (एजेंसी)

पाकिस्तान में सियासी हलचल इस वक्त बेहद तेज है। इमरान खान सरकार को कुछ दिन की और मोहलत मिल गई है। नेशनल असेंबली के अंदर इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। लेकिन नेशनल असेंबली का सत्र शुरू होते ही 3 अप्रैल तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। विपक्षी दलों के सदस्यों के विरोध के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इमरान खान को 3 दिन का वक्त मिल गया है। पल-पल बदलते पाकिस्तान की सियासत को देखते हुए इसे बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इमरान को मिले इन तीन दिनों के जरिये वो अपनी कुर्सी बचाने के प्रयास तेज कर सकते हैं।

पाक मंत्री ने नवाज शरीफ के भारत-इस्राइल के बीच सांठगांठ का लगाया आरोप

पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) की बैठक इस बात का सबूत दिखाने के लिए बुलाई गई थी कि कैसे बाहर से पीएम इमरान खान को

सत्ता से हटाने की कोशिश की जा रही है। चौधरी ने आरोप लगाया कि खान के खिलाफ साजिश पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर पर रची गई थी। फवाद चौधरी ने कहा, 'यह राष्ट्रीय संप्रभुता की लड़ाई है। हम जानते हैं कि प्रमुख खिलाड़ी कौन हैं, भारत और इजरायल के साथ उनके संबंध। नवाज शरीफ की भारतीय और इजरायली अधिकारियों के साथ मुलाकात छिपी नहीं है।'

बिलावल भुट्टो ने दी पीएम को इस्तीफा देने की सलाह

इमरान खान की तरफ से विपक्ष को प्रस्ताव दिया गया कि अगर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को वापस ले लिया जाता है तो वह असेंबली भंग कर देंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए असेंबली सत्र से पहले विपक्षी नेताओं की बैठक में यह बात सामने आई। लेकिन पीपीपी पीपीपी प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कहा गया कि हम इमरान खान को कोई एनआरओ नहीं देंगे और न ही अविश्वास प्रस्ताव वापस लेंगे। प्रधानमंत्री को केवल यही सलाह है कि आज इस्तीफा दें और विपक्ष के नेता को विश्वास मत लेने दें।

विश्व में घट रहे कोरोना के केस, पर मौतों में 40 फीसदी का इजाफा : डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट

जिनेवा (एजेंसी)

महामारी कोरोना का संक्रमण लगातार वैश्विक स्तर पर लगातार घट रहा है। पिछले सप्ताह कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में गिरावट देखी गई जबकि संक्रमण से मौत के मामलों में 40 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की जारी ताजा रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। महामारी को लेकर अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि डब्ल्यूएचओ के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र, जहां दिसंबर अंत से मामलों में वृद्धि देखी जा रही थी, समेत हर जगह पर संक्रमण के नए मामलों में कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले सप्ताह दुनियाभर में कोविड-19 के करीब एक करोड़ नए मामले सामने आए और 45,000 मरीजों ने दम तोड़ दिया। हालांकि, इससे पिछले सप्ताह मौत के मामलों में 23 फीसदी की कमी दर्ज की गई थी। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, पिछले सप्ताह कोविड-19 मरीजों की मौत के मामलों में वृद्धि का कारण चिली और अमेरिका में इस तरह के मामलों को दर्ज करने की प्रक्रिया में बदलाव होना रहा। इसके अलावा, भारत के महाराष्ट्र में 4,000 से अधिक मौत के मामलों को जोड़े जाने से भी मृतक संख्या में वृद्धि दर्ज की गई क्योंकि पहले इस संख्या को कोविड-19 मौत की श्रेणी में नहीं रखा गया था। दूसरी ओर यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 50 से अधिक उम्र के लोगों और कुछ इम्युनोकॉम्प्रोमाइज्ड व्यक्तियों के लिए फाइजर-बायोएनटेक या मॉडर्ना के पांचवें कोविड-19 बूस्टर शॉट को मंजूरी दी है।

रूस के साथ सहयोग की कोई सीमा नहीं: चीन

बीजिंग (एजेंसी)

यूक्रेन युद्ध के बीच बीजिंग का दौरा करने वाले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की मेजबानी करते हुए, चीन ने कहा कि दोनों सहयोगियों के बीच सहयोग की कोई सीमा नहीं है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी 'तास' की खबर के अनुसार अफगानिस्तान पर विदेश मंत्रियों की तीसरी बैठक के लिए लावरोव पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत के टुनक्सी पहुंचे। चीन-रूस संबंधों की सीमाओं का वर्णन करने के लिए पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने यहां एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, 'चीन-रूस सहयोग की कोई सीमा नहीं है, हमारे लिए शांति के लिए प्रयास करने की कोई सीमा नहीं है, हमारे लिए सुरक्षा की कोई सीमा नहीं है और हमारे लिए आधिपत्य का विरोध करने के लिए कोई सीमा नहीं है।' तुर्की के इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच हाल के दौर की बातचीत पर टिप्पणी करते हुए वेनबिन ने दोनों पक्षों द्वारा प्रदर्शित 'सकारात्मक संकेतों' का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, 'हमारा हमेशा से मानना रहा है कि यूक्रेन संकट के समाधान के लिए बातचीत ही एकमात्र सही तरीका है।' समाचार एजेंसी 'तास' के एक पत्रकार द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में चीन, रूस और यूक्रेन के बीच किसी भी समझौते के लिए गारंटी देने वाला हो सकता है, वांग वेनबिन ने कहा कि चीन संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी पक्षों को प्रोत्साहित करता है। उन्होंने कहा, 'हम इस दिशा में सभी राजनयिक प्रयासों का समर्थन करते हैं।' बाद में लावरोव ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ अपनी बैठक में कहा कि रूस चीन के साथ स्थिर और सुसंगत तरीके से संबंध बनाने में रुचि रखता है। शीर्ष रूसी राजनयिक ने कहा, 'हम चीन के साथ अपने संबंधों को लगातार विकसित करने में रुचि रखते हैं, हमारे नेताओं - रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने इस पर सहमति व्यक्त की है।

बुरी तरह फेल हुई चीन की जीरो कोविड पॉलिसी, सभी 31 प्रांतों में फैला कोरोना, शंघाई समेत 5 शहरों में लॉकडाउन

बीजिंग (एजेंसी)

कोविड-19 महामारी के रोकथाम को लेकर चीन ने कई सख्त पाबंदियां लगाई, जीरो कोविड पॉलिसी लगाई की और लोगों को घरों में कैद भी किया। लेकिन तमाम कवायदों के बावजूद ड्रैगन के देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। देखते ही देखते कोरोना वायरस चीन के सभी 31 प्रांतों में फैल चुका है। ऐसा दो साल में पहली दफा हुआ है कि चीन के सभी प्रांतों में कोरोना का असर देखने को मिला है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमितों का आंकड़ा 62 हजार के पार पहुंच चुका है। कोरोना के तेजी से फैलते प्रवाह को देखते हुए चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई समेत 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है।

शंघाई समेत 5 शहरों में लॉकडाउन

चीन में कोरोना के प्रकोप को इस तरह से समझ सकते हैं कि करीब 12 हजार सरकारी अस्पतालों में नए मरीजों को भर्ती करने की जगह नहीं है। चीन ने कोरोना की पहली लहर के दौरान सख्त लॉकडाउन का नियम बनाया था। जिसके तहत एक भी केस आने पर पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया जाता था। ऐसे में उसके चिकित्सा ढांचे पर काफी प्रभाव पड़ा। चीन की आर्थिक राजधानी और

2.6 करोड़ की आबादी वाले सबसे बड़े शहर शंघाई ने इससे पूर्व कोविड के मामले आने पर सीमित लॉकडाउन लगाया था जिनमें रिहायशी परिसरों और कार्य स्थलों को बंद किया गया था।

सर्वाधिक टीकाकरण वाले देशों की सूची में शामिल

चीन दुनिया के सर्वाधिक टीकाकरण वाले देशों की सूची में शामिल है। चीन में 88 प्रतिशत से अधिक आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। लेकिन इसके बावजूद चीन के 60 साल के अधिक उम्र के लोगों में से केवल 52 प्रतिशत को ही दोनों डोज लग पाई है। चीन में इस महीने 56,000 से अधिक संक्रमण के मामले सामने आए, जिनमें से अधिकतर मामले जिलिन में सामने आए हैं। जिलिन ने कई शहरों में यात्रा प्रतिबंध और आंशिक लॉकडाउन लगाया है जिसमें चांगचुन भी शामिल है। चीन ने वैश्विक महामारी के खिलाफ ह्यजीरो कोविड पॉलिसीह्न की रणनीति अपनाई है, जिसके चलते मामले बढ़ने पर अधिकतर आर्थिक गतिविधियां बाधित कर दी जाती हैं।

अमेरिका ने चेताया- रूस से तेल खरीद बढ़ाने का भारत को भरना पड़ सकता है भारी खमियाजा

वॉशिंगटन (एजेंसी)

रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच अमेरिका ने रूस पर 5,000 से ज्यादा छोटे-बड़े प्रतिबंध लगाएं हैं। इसमें तेल की खरीद भी शामिल हैं। अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद भी रूस ने भारत को सस्ते कच्चे तेल का ऑफर दिया है, जिसे भारत लगभग स्वीकार करने की स्थिति में है। भारत का ये कदम कूटनीतिक रूप से अमेरिका के लिए एक झटका है। ऐसे में अमेरिका ने भारत के चेताया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि भारत को रूस से तेल का आयात बढ़ाने के कारण 'बड़े खतरे' का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका रूस पर लगे प्रतिबंधों को लागू करवाने में ज्यादा सख्ती बरतने के लिए कदम उठा रहा है। अमेरिकी अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया, अमेरिका को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि भारत रूस से तेल खरीदे। बशर्ते वह इसे डिस्काउंट पर खरीद रहा है। आयात पिछले सालों के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं रहा है। आयात का थोड़ा बहुत बढ़ना ठीक है।

अधिकारी ने आगे कहा, 'अमेरिका ने रूस पर फिलहाल जो प्रतिबंध लगाए हैं, वे किसी देश को रूस से तेल खरीदने से नहीं रोकते। लेकिन ऐसे संकेत हैं कि अमेरिका अन्य देशों को पाबंदियों के दायरे में ला सकता है, ताकि रूस को मिलने वाली मदद बंद की जा सके। अमेरिकी अधिकारी का ये बयान ऐसे समय में आया है, जब रूस के विदेश मंत्री सर्गई लावरोव भारत दौरे पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के आर्थिक सुरक्षा मामलों के उप सलाहकार दलीप सिंह भी भारत दौरे पर आने की बात कह चुके हैं। बुधवार को जर्मनी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारत का दौरा किया था और गुरुवार को ब्रिटिश विदेश मंत्री भारत पहुंच रही हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है। यूक्रेन पर हमले के बाद भारत ने रूस से तेल आयात बढ़ा दिया है। 24 फरवरी के बाद से ही भारत ने 1.3 करोड़ बैरल तेल खरीदा है, जबकि पिछले पूरे साल में उसका रूस से तेल आयात 1.6 करोड़ बैरल था।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार भारत और रूस के बीच तेल खरीद को लेकर चल रही बातचीत के बारे में जानती है। प्रवक्ता ने कहा, 'हम भारत और बाकी दुनिया में हमारे साझीदारों के साथ लगातार संपर्क में हैं, ताकि रूस पर यूक्रेन में विनाशकारी युद्ध जल्द से जल्द खत्म करने के लिए दबाव डालने के लिए एक साझी और मजबूत कार्रवाई की जा सके, जिसमें सख्त प्रतिबंध लगाना भी शामिल है।'

अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि भारत रूस के साथ व्यापार डॉलर में ना करके रूबल में करे, बशर्ते लेनदेन में प्रतिबंधों के नियमों का पालन किया जाए। भारत और रूस रूबल-रुपये में लेनदेन की प्रक्रिया तैयार करने पर काम कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी ने कहा, 'वे जो भी भुगतान करें, जो भी करें वह प्रतिबंधों के दायरे में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वे बड़ा खतरा उठा रहे हैं। जब तक कि वे प्रतिबंधों का पालन

करते हैं और खरीद की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है।'

केंद्र ने नागालैंड, असम और मणिपुर में अफस्पा का क्षेत्र घटाया : शाह

नई दिल्ली, 31 मार्च (एजेन्सी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम के तहत दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) के तहत अशांत क्षेत्रों को कम किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन अलग-अलग ट्वीट्स में बहुप्रतीक्षित निर्णय की घोषणा ऐसे समय पर की है, जब अधिकांश राजनीतिक दल और गैर सरकारी संगठन अफस्पा को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। पिछले साल 4 और 5 दिसंबर को नागालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों द्वारा 14 लोगों के मारे जाने और 30 अन्य के घायल होने के बाद इसे निरस्त करने की मांग और तेज हो गई थी।

शाह ने ट्विटर पर घोषणा करते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार के लगातार प्रयासों से तथा पूर्वोत्तर में सुरक्षा स्थिति में सुधार के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम के तहत दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्रों को कम किया है।'

उन्होंने कहा, 'अफस्पा के तहत क्षेत्रों में कमी सुरक्षा की स्थिति में सुधार और प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर पूर्व में स्थायी शांति लाने और उग्रवाद को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयासों और कई समझौतों के कारण तेजी से विकास का परिणाम है।'

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का निर्णय लिया है। एक अन्य ट्वीट में अमित शाह ने इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने लिखा, 'पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र, जो दशकों से उपेक्षित था, अब शांति, समृद्धि और अभूतपूर्व विकास के एक नए युग का गवाह बन रहा है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर पूर्वोत्तर के लोगों को बधाई देता हूं।'

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह, त्रिपुरा के उनके समकक्ष बिप्लब कुमार देब और नागालैंड के समकक्ष नेफ्यू रियो ने सबसे पहले केंद्र की घोषणा का स्वागत किया।

सिंह ने ट्वीट किया, 'माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि नमन। मणिपुर, असम और नागालैंड के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का निर्णय लिया है।'

देब ने अपने ट्वीट में कहा, 'मैं असम, नागालैंड और मणिपुर के लिए अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने के कदम का स्वागत करता हूं। इससे पूर्वोत्तर का और विकास सुनिश्चित होगा।'

बता दें कि अफस्पा सेना और अन्य केंद्रीय अर्ध-सैन्य बलों को बिना किसी पूर्व सूचना या गिरफ्तारी वारंट के कहीं भी छापेमारी, अभियान चलाने, किसी को भी गिरफ्तार करने की अनुमति देता है। यह कानून पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में लागू है।

रियो ने अपने ट्वीट में कहा, 'नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत सरकार का आभारी हूं। यह उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।'

पूर्वोत्तर क्षेत्र में त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां मई 2015 में मुख्यमंत्री माणिक सरकार के नेतृत्व वाली तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने आतंकी गतिविधियों पर काबू पाने के बाद अफस्पा को वापस ले लिया था।

अफस्पा को 2018 में मेघालय के सीमावर्ती क्षेत्रों से भी हटा लिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय समय-समय पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करते हुए अफस्पा की अवधि को छह महीने से बढ़ाकर एक साल कर देता है।

नागालैंड विधानसभा ने पिछले साल दिसंबर में एक विशेष सत्र में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें केंद्र से पूरे पूर्वोत्तर और विशेष रूप से नागालैंड से अफस्पा को निरस्त करने की मांग की गई थी, ताकि नागा समुदाय से जुड़े मुद्दे के शांतिपूर्ण राजनीतिक समाधान खोजने के लिए चल रहे प्रयासों को मजबूत किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने शरद यादव को सरकारी बंगला खाली करने की समय सीमा 31 मई तय की

नई दिल्ली, 31 मार्च (एजेन्सी)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को सांसद के तौर पर दिल्ली में उन्हें आवंटित सरकारी बंगला खाली करने के लिए 31 मई तक का समय दिया है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने यादव की तबीयत पर ध्यान दिया और मानवीय आधार पर सरकारी आवास खाली करने के लिए समय बढ़ाया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि 75 वर्षीय यादव को एक हलफनामा दाखिल करना चाहिए कि वह इस साल 31 मई के बाद परिसर खाली कर देंगे।

इसने स्पष्ट किया कि यह अयोग्यता की वैधता के मुद्दे पर नहीं गया है, जो उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है और यादव की याचिका को 31 मई तक सरकारी बंगला खाली करने का समय देकर निपटाया जा रहा है।

28 मार्च को शीर्ष अदालत ने केंद्र से मानवीय आधार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर विचार करने के लिए कहा था, जिसमें उन्हें 15 दिनों के भीतर घर खाली करने का निर्देश दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने नोट किया था कि उन्हें 2017 में राज्यसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था और इसलिए आधिकारिक निवास को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है।

शीर्ष अदालत में यादव का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि अयोग्यता को चुनौती देने वाली अपील अभी भी लंबित है।

उन्होंने कहा, 'वैसे भी उनका कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो रहा है। इसलिए, वह एक वचन देंगे कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह बंगला खाली हा जाएगा। वह वेंटिलेटर पर थे, उन्हें हर दिन डायलिसिस के लिए जाना पड़ता था। वह हिल भी नहीं सकते थे।'

केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने प्रस्तुत किया कि सरकार सांसदों और मंत्रियों के लिए घरों की कमी का सामना कर रही है और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद, कमी और अधिक बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि बिहार के एक सांसद को आधिकारिक आवास आवंटित किया गया है और जुलाई में केवल कुछ महीने दूर हैं।

पीठ ने जैन से कहा, 'हम इसकी राजनीति या व्हिप आदि के उल्लंघन पर नहीं हैं, बल्कि उनकी चिकित्सा स्थिति के आधार पर विशुद्ध रूप से मानवीय आधार पर किसी तरह की सोच रहे हैं।'

इसने यादव के वकील से पूछा, 'हमें एक उचित समय बताएं, जिसके द्वारा आप बंगला खाली कर सकते हैं। हम सुनवाई स्थगित कर देंगे।' पीठ ने जैन को मानवीय आधार पर मामले पर विचार करने के लिए सरकार से निर्देश लेने को भी कहा।

उच्च न्यायालय ने 15 मार्च को यादव को यहां 7, तुगलक रोड स्थित बंगला 15 दिन के भीतर सरकार को सौंपने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा कि उन्हें एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए चार साल से अधिक समय बीत चुका है। यादव ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि वह 22 साल से वहां रह रहे हैं और राज्यसभा से उनकी अयोग्यता की वैधता को चुनौती अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

याचिका में कहा गया है कि उनका मामला उनके खराब स्वास्थ्य के कारण 'सहानुभूतिपूर्ण उपचार का हकदार है' और बताया कि जुलाई 2020 से उन्हें 13 बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आखिरी बार फरवरी में उन्हें छुट्टी दे दी गई थी।

मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी, अप्रैल में सामान्य से अधिक तापमान का अनुमान

नई दिल्ली, 31 मार्च (एजेन्सी)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गुरुवार को कहा कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में जारी दूसरी गर्मी की लहर के साथ ही अप्रैल में उत्तर पश्चिम के अधिकतर भागों और मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज होने की संभावना है।

आईएमडी ने कहा कि देश के शेष हिस्सों में सामान्य से कम अधिकतम तापमान की संभावना है।

आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने अप्रैल के लिए तापमान और वर्षा के आउटलुक की घोषणा करते हुए कहा कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, मध्य भारत के पूर्वी हिस्सों और पूर्वोत्तर भारत के दक्षिणी हिस्से में सामान्य न्यूनतम तापमान की संभावना है।

मार्च में गर्मी की लहरों के दो दौर देखे गए, पहला 11-21 मार्च के बीच जबकि दूसरा 26 मार्च को शुरू हुआ और अभी भी जारी है।

इस बीच, तटीय प्रायद्वीपीय क्षेत्रों को छोड़कर, लगभग पूरे भारत में मार्च में कम वर्षा हुई।

आईएमडी ने कहा, देश में अप्रैल में औसत बारिश सामान्य (लंबी अवधि के औसत का 89-111 फीसदी) रहने की संभावना है।

उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि दक्षिण प्रायद्वीप के कई हिस्सों, पश्चिम मध्य भारत के आसपास के इलाकों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक सामान्य बारिश होने की संभावना है।

रूसी विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचे, आज जयशंकर से करेंगे वार्ता

नई दिल्ली, 31 मार्च (एजेन्सी)। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव कच्चे तेल की पेशकश, रुपये-रूबल भुगतान और हथियारों के सौदे पर भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर के साथ बातचीत करने के लिए गुरुवार शाम नई दिल्ली पहुंचे। यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद भारत में किसी शीर्ष रूसी राजनेता की यह पहली उच्च स्तरीय यात्रा है।

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव शाम छह बजे दिल्ली पहुंचे। लावरोव शुक्रवार दोपहर जयशंकर से मुलाकात करेंगे और शाम 5.50 बजे मॉस्को के लिए उड़ान भरेंगे।

जैसे ही अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों और कुछ रूसी बैंकों को स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से हटाया जा रहा है, लावरोव कच्चे तेल के लिए रुपये-रूबल मूल्यवर्ग के भुगतान के तरीके पर विचार करेंगे, जो रूस ने भारत को दिया है। नई दिल्ली रूसी तेल को रियायती दर पर खरीदने के खिलाफ नहीं है। यह भी कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी रुपये-रूबल भुगतान पर चर्चा करने के लिए अपने रूसी समकक्षों से मिलने वाले हैं।

युद्ध की शुरुआत के बाद से, भारत पर पश्चिम और उसके सहयोगियों के दबाव में रूस के खिलाफ एक मजबूत रुख अपनाने का दबाव रहा है।

चूंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में भारत की सैन्य क्षमताओं को भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों, ग्रिगोरोविच क्लास फ्रिगेट्स, फाइटर जेट्स, ट्रायम्फ एस-400, एके 203 असॉल्ट राइफल और अन्य जैसे कई प्लेटफार्मों की डिलीवरी में देरी होने की उम्मीद है। भारतीय नेता इस मुद्दे पर लावरोव के साथ चर्चा करेंगे।

भारत ने अपने सैन्य बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने का फैसला किया है, जब जुलाई 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ देश चीन के साथ विवाद में उलझा हुआ है और दोनों देशों की सेना अग्रिम स्थानों पर लंबे समय से आमने-सामने रही है। चीन और पाकिस्तान से दो-मोर्चों पर युद्ध के खतरे ने भारत को बड़े पैमाने पर इस दिशा में कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। हथियारों के सौदे को लेकर रूस अभी भी भारत के सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ताओं में से एक है।

भारत के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में रूस के साथ मौजूदा सौदों की स्थिति और युद्ध की सैन्य क्षमताओं को कैसे प्रभावित करने जा रहा है, इसकी समीक्षा की है।

दिसंबर 2021 में, भारत और रूस ने विभिन्न क्षेत्रों में दो दर्जन से अधिक सौदों पर हस्ताक्षर किए और 10 साल के रक्षा सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए।

भारत यह सुनिश्चित करेगा कि रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण ये सौदे अधर में अटके या विलंबित न हों।

राज्यसभा से रिटायर हुए 72 सांसद, पीएम मोदी ने दी विदाई

नई दिल्ली, 31 मार्च (एजेन्सी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा के 72 सेवानिवृत्त सदस्यों की विदाई के मौके पर सदन में बोलते हुए उनको शुभकामनाएं दीं और सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों के बेहतर भविष्य की कामना की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों के बेहतर भविष्य की कामना करते हुए गुरूवार को उनसे आग्रह किया कि वह अपने अनुभवों को चारों दिशाओं में ले जाएं और अपने योगदानों को कलमबद्ध कर देश की भावी पीढ़ी को प्रेरित करें।

राज्यसभा से मार्च और जुलाई के बीच 72 सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनमें कांग्रेस के ए के एंटनी, आनंद शर्मा, अंबिका सोनी, भारतीय जनता पार्टी के सुरेश प्रभु, सुब्रमणियम स्वामी, बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा, शिवसेना के संजय राउत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल सहित कई अन्य सदस्य शामिल हैं।

सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों में निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह जैसे मंत्री भी हैं।

प्रधानमंत्री ने सेवानिवृत्त हो रहे सांसदों के लिए दिए गए अपने विदाई भाषण में उच्च सदन में कहा कि जो सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके पास अनुभव की बहुत बड़ी पूंजी है और कभी-कभी ज्ञान से ज्यादा अनुभव की ताकत होती है। उन्होंने कहा कि ज्ञान की तो अपनी सीमाएं होती हैं, वह सम्मेलनों में काम भी आता है लेकिन अनुभव से जो प्राप्त होता है, उसमें समस्याओं के समाधान के लिए सरल उपाय होते हैं।

उन्होंने कहा कि अनुभव से गलतियों में कमी आती है।

प्रधानमंत्री ने कहा, सदस्यों का

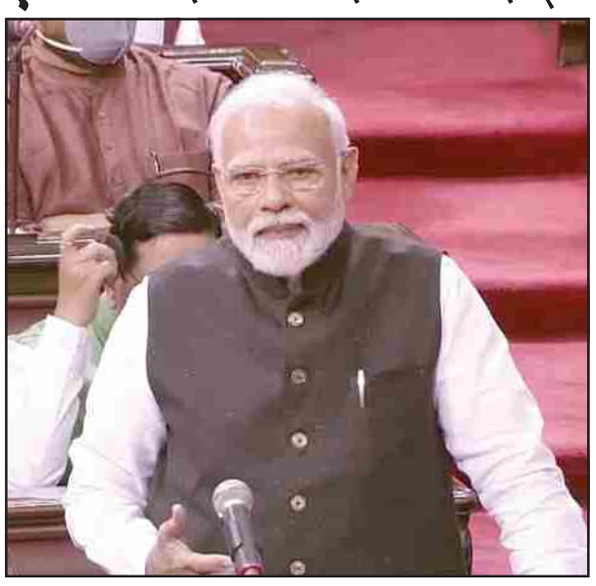

कहा- आप फिर इस सदन में आएं यही मेरी कामना है

अनुभव देश की समृद्धि में बहुत काम आएगा क्योंकि उन्होंने एक लंबा समय सदन की चारदिवारियों में बिताया है। इस सदन में हिंदुस्तान की कोने-कोने की भावनाओं का प्रतिबिंब, वेदना और उमंग सबका एक प्रवाह बहता रहता है।

उन्होंने कहा, भले हम इन चार दीवारों से निकल रहे हैं लेकिन इस अनुभव को राष्ट्र के सर्वोत्तम हित के लिए चारों दिशाओं में ले जाएं। चारों दीवारों में पाया हुआ सब कुछ चारों दिशा में ले जाएं।

प्रधानमंत्री ने सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों से कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान सदस्यों ने सदन में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया और उस योगदान ने देश को आकार और एक दिशा देने में भूमिका निभाई है तो उसे जरूर कलमबद्ध करें।

उन्होंने कहा, मैं चाहूंगा उन स्मृतियों को आप कहीं ना कहीं लिखें ताकि कभी न कभी वह आने वाली पीढ़ियों के काम आए। हर किसी ने कुछ न कुछ कोई योगदान दिया होगा, जिसने देश को दिशा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभायी होगी। हम इसको अगर संग्रहित करेंगे तो हमारे पास एक मूल्यवान खजाना होगा।

देश की आजादी के 75 साल के अवसर पर मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महापुरुषों ने देश के लिए बहुत कुछ दिया है, अब देने की जिम्मेदारी हमारी है।

उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि आजादी के अमृत महोत्सव के पर्व को माध्यम बनाकर वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने में अपना योगदान दें।

उन्होंने सदस्यों से कहा, आपके इस योगदान से देश को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। देश को लाभ मिलेगा। मैं सभी साथियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

भारत में ईवी की बिक्री में 162 प्रतिशत का इजाफा : गडकरी

नई दिल्ली, 31 मार्च (एजेन्सी)। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि इस साल इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी)की बिक्री में 162 प्रतिशत की तेजी देखी गयी है।

केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में प्रश्न काल के दौरान एक प्रश्न का उत्तर देते हुये सदन को बताया कि वार्षिक आधार पर ईवी की बिक्री में तेजी आयी है।

उन्होंने बताया कि श्रेणी आधार पर दोपहिया ईवी की बिक्री में 423 प्रतिशत, तिपहिया ईवी में 75 प्रतिशत और चारपहिया ईवी में 238 प्रतिशत की तेजी आयी है। बसों की बिक्री में 1,250 प्रतिशत की तेजी आयी है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस साल 13 मार्च तक देश में 10,95,746 ईवी पंजीकृत हैं और 1,742 चार्जिंग स्टेशन संचालित हैं।

गडकरी ने बताया कि करीब 85 प्रतिशत लिथियम आयन बैट्री देश में बनायी जा रही है। इसके लिये मानक तय किये गये हैं और अगर कोई निर्माता तय मानक के अनुसार, निर्माण नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

उन्होंने बताया कि ईवी की चार्जिंग के लिये सरकार स्वच्छ ऊर्जा इस्तेमाल करने पर जोर दे रही है। सरकार की नीति सभी नये शोधों को महत्व देने की है ताकि ग्राहकों के लिये अधिक किफायती नये स्टार्टअप को अवसर मिल सके।

गडकरी ने बताया कि एनएचएआई प्रत्येक 40 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन विकसित कर रही है और इसके लिये पवन और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है।

स्टालिन ने पीएम मोदी से की मुलाकात, फुटवियर क्षेत्रा के लिए पीएलआई योजना लाने की मांग की

नई दिल्ली, 31 मार्च (एजेन्सी)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने फुटवियर निर्माण क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) लाने की जरूरत बताई।

उन्होंने राज्य में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) प्रयोगशाला की स्थापना, सहमति के अनुसार पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति और राज्यों के साथ उपकर और अधिभार साझा करने पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान स्टालिन ने राज्य की विभिन्न मांगों को सूचीबद्ध करते हुए एक ज्ञापन सौंपा।

स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर फुटवियर उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जो राष्ट्रीय विनिर्माण उत्पादन का 26 प्रतिशत और राष्ट्रीय निर्यात का 45 प्रतिशत हिस्सा है।

फुटवियर निर्माण के लिए एक पीएलआई योजना मौजूदा खिलाड़ियों की उत्पादकता में वृद्धि करेगी और भारत को फुटवियर निर्यातकों के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बनाएगी।

स्टालिन ने कहा कि यह योजना इसके अलावा आभूषण, जिपर, तलवों, बकल और अलंकरण जैसे इनपुट उत्पादों के लिए आयात प्रतिस्थापन में सहायता करेगी।

स्टालिन ने सलेम स्टील प्लांट के पास 1,507.23 एकड़ अतिरिक्त भूमि का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से इसे स्थानांतरित करने का आग्रह किया, ताकि इसका उपयोग रक्षा औद्योगिक पार्क के लिए किया जा सके।

कोल इंडिया द्वारा थर्मल प्लांटों के लिए कोयले की आपूर्ति में कमी की ओर इशारा करते हुए स्टालिन ने कहा कि बिजली मंत्रालय/कोयला मंत्रालय से सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड से 40.2 लाख टन प्रतिवर्ष कोयला आवंटित करने का अनुरोध किया जा सकता है।

स्टालिन ने मोदी से यह भी आग्रह किया कि केंद्र सरकार को उपकर और अधिभार की वसूली को उलट देना चाहिए और ऐसे सभी उपकरों और अधिभारों को कर की मूल दर के साथ मिला देना चाहिए, ताकि राज्यों को राजस्व का उनका वैध हिस्सा प्राप्त हो सके।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक : सत्येन्द्र नाथ सिंह एवं मुद्रकः नूतन वर्मा द्वारा प्राइम प्रिंटर्स, प्रिमुला कॉटेज, चर्च रोड, गंगटोक से मुद्रित एवं रतना निवास, मेट्रो प्वाइंट, नेशनल हाईवे 10, गंगटोक (पूर्व सिक्किम) से प्रकाशित।
सम्पादक - सत्येन्द्र नाथ सिंह, कार्यकारी सम्पादक - अश्विनी आनंद, मोबाइल नं. : 9474355832, 9609024017, फोन नं. : 03592-204174, पोस्टल रजि. सं. : WB/SKM/110/07-09, e-mail ID : anugamini@gmail.com